RNI. NO. RAJHIN/2021/82156

डाक पंजीयन संख्याः RJ/ALW/866/2023

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा

जज्बा सच दिखाने का

वर्ष -05 | अंक -331 | मूल्यः 2.00 रू. | अलवर, शुक्रवार 13 फरवरी, 2026 | प्रभात संस्करण | कुल पेज- 8

WWW.Voiceofpratigya.com | Twitter.com/Voiceofpratigya | facebook.com/Voiceofpratigya | YouTube.com/Voiceofpratigya | Instagram- Instagram.com/Voiceofpratigya | 9414508610 | pratigya.alwar@gmail.com

राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो, आजीवन चुनाव लड़ने पर बैन लगेः निशिकांत दुबे

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा नई दिल्ली

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हालिया भाषण को लेकर राजनीतिक विवाद सातवें आसमान पर पहुंच गया है। हालांकि अब यह भी साफ हो गया है कि राहुल गांधी के सामने से एक बड़ी मुसीबत टल गई है। इसका बड़ा कारण है कि राहुल गांधी के खिलाफ सरकार विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाएगी, लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि यह मामला अभी तक पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार को राहुल गांधी के द्वारा लोकसभा में दिए गए भाषण पर कड़ी आपत्ति जताते हुए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की मांग की थी। सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के इरादे में नहीं है। हालांकि, बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने कल लोकसभा में जो भाषण दिया था, उसमें कही गई कुछ बातें और आरोप प्रमाणित नहीं थे। ऐसे में संभावना इस बात की तेज हो गई है कि राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए भाषण के कुछ अंश सदन की कार्यवाही से हटाए जा सकते हैं।

भाषण के कुछ हिस्से हटाने की मांग

भाजपा राहुल के भाषण कुछ हिस्सों को लेकर आपत्ति जता रही है। पार्टी के चीफ विप संजय जायसवाल ने बजट चर्चा के दौरान राहुल गांधी द्वारा कही गई कुछ बातों को लोकसभा की कार्यवाही से हटाने का औपचारिक नोटिस दिया है। भाजपा का कहना है कि उनके कुछ बयान आपत्तिजनक और तथ्यों से परे हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ एक अलग मूल प्रस्ताव दायर किया है। यह सामान्य नोटिस से अलग प्रक्रिया होती है। अगर लोकसभा अध्यक्ष इसे स्वीकार करते हैं, तो इस पर सदन में चर्चा और मतदान हो सकता है। ऐसे में प्रस्ताव पारित होने पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता जा सकती है।

लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र

बता दें कि इस पूरे मामले में निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर मांग की है कि राहुल गांधी के कथित 'अनैतिक आचरण' की जांच के लिए एक संसदीय समिति बनाई जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने पर विचार किया जाए। दुबे का आरोप है कि राहुल गांधी ने संसद के अंदर और बाहर ऐसे बयान दिए हैं, जिससे देश की एकता और संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंची है।

कांग्रेन ने भी दिया करारा जवाब

गौरतलब है कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भाजपा पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के शब्दों को कार्यवाही से हटा दिया गया, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समान बयान रिकॉर्ड में बने हुए हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि पिछली बार राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की गई थी, लेकिन जनता ने उन्हें और बड़े अंतर से चुनकर संसद में भेजा। उन्होंने कहा कि हमें किसी नोटिस से फर्क नहीं पड़ता। चाहें तो हमें फांसी पर लटका दो। फिलहाल मामला लोकसभा अध्यक्ष के पास है और आगे की कार्रवाई उनके फैसले पर निर्भर करेगी।

राहुल गांधी के खिलाफ क्या प्रस्ताव

झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को लोकसभा स्पीकर को अपना नोटिस देने के बाद कहा,'कोई प्रिविलेज मोशन नहीं है, मैंने एक सब्सटेंटिव मोशन दिया है, किसी एमपी के खिलाफ आरोप लगाते हैं...क्योंकि उनकी तरह कानून की हत्या करने वाला आदमी नहीं हूं या उनकी तरह दादागिरी से ये संविधान चलाने की बात नहीं है।'

राहुल गांधी किस तरह के आरोप हैं

निशिकांत दुबे ने आगे बताया, 'मैंने एक सब्सटेंटिव मोशन दिया है। उसमें मैंने ये जिक्र किया है कि कैसे ये सोरोस फाउंडेशन के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ, यूएसऐड के साथ मिलकर थाईलैंड जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं, वियतनाम जाते हैं,अमेरिका जाते हैं, भारत-विरोधी ताकतों के साथ किस तरह से मिले हुए रहते हैं। इनकी सदस्यता भी रद्द हो और इनको जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित भी कर दिया जाए।'

मोदी सरकार पर आक्रामक हैं राहुल

दरअसल, राहुल गांधी ने बजट सत्र में मोदी सरकार के साथ संसद में संग्राम छेड़ रखा है। वह और उनकी पार्टी स्पीकर से भी उलझने में नहीं हिचकिचाए हैं। बुधवार को राहुल ने तो भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर लोकसभा में मोदी सरकार पर देश बेच देने तक का आरोप मढ़ दिया।

सब्सटेंटिव मोशन क्या होता है

संसदीय व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों को कई तरह के विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। इसी में से एक सब्सटेंटिव मोशन भी है। यह एक स्वतंत्र और किसी खास मुद्दे के लिए दिया जाने वाला नोटिस है, जिसमें सांसदों की सदस्यता रद्द करने से लेकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने या मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाने की मांग की जा सकती है। अब यह लोकसभा स्पीकर पर निर्भर है कि वह दुबे के मोशन पर क्या कार्रवाई करते हैं। स्पीकर की मंजूरी के बाद यह प्रस्ताव के रूप में सदन में लाया जा सकता है और फिर संसद तय करेगी कि उसपर आगे क्या कदम उठाए जाएं।

एफआईआर हो, मुकदमा दर्ज हो या विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएं, मैं किसानों के लिए लड़ूंगाः राहुल गांधी

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा नई दिल्ली

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि उनके खिलाफ चाहे एफआईआर दर्ज हो या मुकदमा या विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाए वो किसानों के लिए लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। नेता प्रतिपक्ष का यह बयान तब आया है, जब केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस लाने जा रही है, क्योंकि उन्होंने सदन को गुमराह किया और बिना आधार के गंभीर आरोप लगाए। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ "विशिष्ट प्रस्ताव" लाने के लिए एक नोटिस दिया है। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की सदन की सदस्यता रद्द करने और उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की मांग की है। इससे पहले, संसद में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को लेकर राहुल गांधी गुरुवार को पत्रकारों पर भड़क गए। उन्होंने पत्रकारों से अपने काम में 'उद्देश्यपूर्ण बने रहने' और अपने पेशे की पवित्रता बनाए रखने को कहा। राहुल गांधी के भाषण को लेकर सत्तापक्ष की तरफ से लोकसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की चर्चाएं थीं। हालांकि, बाद में सत्तापक्ष ने इस प्रस्ताव को लाने से साफ इनकार कर दिया। जब राहुल गांधी से विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर सवाल पूछा गया, तो वे मीडिया के कुछ लोगों पर भड़क गए। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, 'आप पूरी तरह से भाजपा के लिए काम नहीं करते। कम से कम थोड़ी 'उद्देश्यपूर्ण' रिपोर्टिंग करने की कोशिश करें। आप जिम्मेदार लोग हैं। आप मीडिया वाले हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप 'उद्देश्यपूर्ण' रहें। आप हर दिन उनके (भाजपा) दिए गए एक शब्द पर अपना पूरा शो नहीं चला सकते। ' बुधवार को, लोकसभा में उस समय विरोध हुआ जब राहुल गांधी ने सरकार की तीखी आलोचना की, जिसमें उन्होंने विदेशी ताकतों के सामने सरेंडर करने और 'भारत माता' को बेचने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के इस तीखे हमले का सत्तापक्ष ने विरोध किया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की भाषा को असंसदीय बताते हुए आपत्ति जताई। भाजपा नेताओं ने मांग की कि उनके भाषण को सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाए।

राहुल ने ट्रेड डील को किसान विरोधी बताया

भाजपा और सरकार को चाहे यह सच्चाई अच्छी न लगे और उनके खिलाफ जो कुछ भी करना है वह कर ले मगर वे अपनी बातों से एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। सरकार के मंत्रियों-भाजपा नेताओं के सियासी हमलों के बाद गुरूवार शाम एक्स पर जारी वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि जो ट्रेड डील किसानों की रोजी-रोटी छीने, देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे वह किसान-विरोधी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ वे तथा उनकी पार्टी अन्नदाताओं के हितों से किसान विरोधी मोदी सरकार को समझौता नहीं करने देंगे। नेता विपक्ष ने सवाल उठाया कि आखिर सरकार हमेशा किसानों की कुर्बानी देने के लिए क्यों तैयार रहती है।

डील से देश की खाद्य सुरक्षा कमजोर होगी

प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए नेता विपक्ष ने कहा कि पहले अपने अरबपति मित्रों के मुनाफे के लिए काले कानून लाए थे, अब अपने गले से अमेरिकी शिकंजा हटाने के लिए ट्रंप के अमेरिका के लिए भारतीय खेती के दरवाजे खोल दिए हैं और कल इन्हीं सब मित्रों के लिए यही दरवाजे और भी चौड़े किए जाएंगे। समझौते पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस डील में अमेरिकी कृषि उत्पादों पर नॉन टैरिफ बैरियर' हटाने की बात की गई है और यह विदेशी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार का खोलना है जो भारत की खाद्य सुरक्षा और किसानों की रोज़ी-रोटी पर सीधा हमला है। कपास, सोयाबीन, ज्वार, फल और ड्राय फ्रूट्स के किसान पहले ही खतरे में आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत के 99.5 प्रतिशत किसान छोटे और गरीब हैं। उनके पास न पर्याप्त सहायता है, न सब्सिडी, पूरा जोखिम किसान उठाता है। जबकि अमेरिका में खेती बड़े पैमाने पर मशीनों से होती है जिस पर वहां की सरकार भारी सब्सिडी देती है।

संसद से सड़क तक लड़ने का संकल्प दोहराया

राहुल गांधी ने कहा कि सस्ती सब्सिडी वाली अमेरिकी खेती से मुकाबला करने को मजबूर किया गया तो भारतीय किसान उनके सामने टिक नहीं पाएगा और भारत के किसानों को बर्बादी झेलनी पड़ेगी। इस समझौते में किसानों से सलाह नहीं लेने तथा संसद को पूरी जानकारी नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात करने वालों ने उल्टा अब किसानों के भविष्य को ही दांव पर लगा दिया है। ऐसे में देश के अन्नदाताओं की लड़ाई वे संसद से सड़क तक ही नहीं हर मंच से लड़ेंगे ताकि देश की खाद्य सुरक्षा की रक्षा की जा सके।

एपस्टीन पर कांग्रेस के 6 उलझाने वाले सवाल, क्या चक्रव्यूह में फंस जाएंगे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी?

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा नई दिल्ली

कांग्रेस पार्टी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को एप्सटीन के चक्रव्यूह में फंसाने के लिए हर संभव कोशिश में लग गई है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने 6 तीखे सवाल उठाते हुए केंद्रीय मंत्री पर एपस्टीन के अपराधों की गंभीरता को कम आंकने का आरोप लगाया। यह विवाद तब और बढ़ गया जब पुरी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के एक बयान का जवाब देते हुए कहा कि वह 8 वर्षों में 'पेशेवर क्षमता' में एपस्टीन से 'तीन या चार बार' मिले थे और 'तीन मिलियन ईमेल' जारी होने के बाद विवरण पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में थे।

खेरा ने 2014 के ईमेल का हवाला दिया

इसके बाद खेरा ने 4 अक्टूबर, 2014 के कथित ईमेल आदान-प्रदान का हवाला दिया, जो अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों का हिस्सा है। इस बातचीत की कथित शुरुआत का जिक्र करते हुए, उन्होंने ङ्क पर एक पोस्ट में लिखा, 'आज, हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि उनके 'संपर्कों' ने उन्हें रीड हॉफमैन से मिलवाया था। लेकिन उन्होंने जो नहीं कहा, वह ज्यादा मायने रखता है। 4 अक्टूबर, 2014 को,एपस्टीन ने हरदीप को ईमेल किया 'क्या रीड से मुलाकात हुई?' हरदीप सिंह पुरी ने कुछ ही घंटों में जवाब दिया मैं आज दोपहर एक मीटिंग के लिए सैन फ्रांसिस्को में हूं। मेरे दोस्त, तुम तो चीजें करवा देते हो। कोई सलाह? एपस्टीन ने जवाब दिया 'उसे बताओ कि तुम उसकी भारत यात्रा का आयोजन करोगे, ताकि वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लोगों और सोशल नेटवर्किंग गुरुओं से मिल सके।'

खेरा के 6 तीखे सवाल

- एपस्टीन को हरदीप और रीड की मुलाकात होने से पहले ही इसके बारे में कैसे पता चल गया था?
- क्या एपस्टीन ही वह 'संपर्ककर्ता' था जिसने रीड हॉफमैन के साथ मुलाकात करवाई थी?

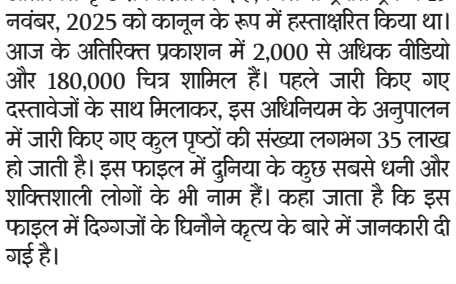

- हरदीप उससे मुलाकात की जानकारी क्यों साझा कर रहे थे?
- एपस्टीन को 'दोस्त' क्यों कहा जा रहा था?
- एपस्टीन हरदीप के लिए क्या कर रहा था?
- अगर उनका संबंध महज संयोगवश या सतही था, तो हरदीप एपस्टीन से 'सलाह' क्यों मांग रहा था?

पवन खेड़ा ने कहा कि देखने में तो ऐसा लगता है कि हरदीप पुरी रीड हॉफमैन की भारत यात्रा की आगे की तैयारियों और व्यवस्थाओं को संभाल रहे थे। लेकिन शुरुआती संपर्क सूत्र - तैयारी की जानकारी देने वाला, बातचीत का समन्वय करने वाला और परिणामों की जानकारी प्राप्त करने वाला - असल में सभी फैसले लेने वाला व्यक्ति जेफरी एपस्टीन था।

क्या है एपस्टीन फाइल

दरअसल, अमेरिकी न्याय विभाग ने दिवंगत यौन अपराधी एपस्टीन से संबंधित फाइल्स के 30 लाख से अधिक अतिरिक्त पृष्ठ प्रकाशित किए हैं, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने 19 नवंबर, 2025 को कानून के रूप में हस्ताक्षरित किया था। आज के अतिरिक्त प्रकाशन में 2,000 से अधिक वीडियो और 180,000 चित्र शामिल हैं। पहले जारी किए गए दस्तावेजों के साथ मिलाकर, इस अधिनियम के अनुपालन में जारी किए गए कुल पृष्ठों की संख्या लगभग 35 लाख हो जाती है। इस फाइल में दुनिया के कुछ सबसे धनी और शक्तिशाली लोगों के भी नाम हैं। कहा जाता है कि इस फाइल में दिग्गजों के घिनौने कृत्य के बारे में जानकारी दी गई है।

अरावली को छूने की किसी को नहीं मिलेगी अनुमति, हरियाणा जू सफारी प्रोजेक्ट पर 'सुप्रीम' रोक

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हरियाणा सरकार के अरावली क्षेत्र में प्रस्तावित जू सफारी प्रोजेक्ट को अनुमति देने से इंकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा कि अरावली को किसी भी कीमत पर छूने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की खंडपीठ ने कहा कि जू सफारी से जुड़े मामले को तब ही देखा जाएगा जब अरावली रेंज की परिभाषा विशेषज्ञों द्वारा स्पष्ट कर दी जाएगी। हरियाणा सरकार की ओर से पेश वकील ने बताया कि उन्होंने प्रोजेक्ट की डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को 10,000 एकड़ से घटाकर 3,300 एकड़ किया है और इसे केंद्रीय सशक्त समिति को प्रस्तुत करना चाहते हैं। खंडपीठ ने कहा हम विशेषज्ञ नहीं हैं। अरावली की परिभाषा विशेषज्ञ तय करेंगे। जब तक परिभाषा अंतिम नहीं होती, हम किसी को अरावली छूने की

अनुमति नहीं देंगे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अरावली केवल हरियाणा या राजस्थान की नहीं है, बल्कि यह कई राज्यों में फैली हुई एक महत्वपूर्ण पर्वतमाला है। उन्होंने यह भी कहा कि विशेषज्ञ समिति की राय आने के बाद ही जू सफारी प्रोजेक्ट पर फैसला लिया जाएगा। पिछले साल अक्तूबर में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावित 'अरावली जू सफारी प्रोजेक्ट' को रोक दिया था। यह प्रोजेक्ट गुड़गांव और नूह जिलों में 10,000 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाना था, जिसमें बड़े बिल्लियों के क्षेत्र, पक्षियों, सरीसृपों और तितलियों के संरक्षण के लिए विशेष जोन शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पांच सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा अधिकारियों और और एक पर्यावरण समूह पीपल फॉर अरावलीज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यह प्रोजेक्ट पहले से ही क्षतिग्रस्त अरावली क्षेत्र के लिए गंभीर खतरा है। न्यायालय ने पहले ही फैसला किया था कि अरावली हिल्स और रेंज की नई परिभाषा के अनुसार किसी भी तरह की खनन गतिविधियों की अनुमति विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने तक नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय की समिति की सिफारिशें स्वीकार की थीं, जिसमें कहा गया कि अरावली हिल वह स्थल होगा जिसकी ऊंचाई स्थानीय स्तर से 100 मीटर या अधिक होगी और अरावली रेंज दो या दो से अधिक ऐसे हिल्स का संग्रह होगी, जो 500 मीटर की दूरी पर होंगे।

केरल चुनावः कांग्रेस ने कसी कमर, रमेश चेन्निथला चुनाव समिति के अध्यक्ष, शशि थरूर को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा नई दिल्ली

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कैंपेन कमेटी और मैनिफेस्टो कमेटी बनाने के प्रस्ताव को तुरंत प्रभाव से मंजूरी दे दी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने अभियान समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी रमेश चेन्निथला को दी है। वहीं डॉ. शशि थरूर को सह-अध्यक्ष बनाया है, शफी परम्बिल को संयोजक, हिबी ईडन, रोजी एम जॉन, सी.आर. महेश, मैथ्यू कुझालनादन, राम्या हरिदास, एम. लिजू, दीप्ति मैरी वर्गीस समिति की सदस्य बनाई गई हैं। शशि थरूर की नियुक्ति का महत्व इसलिए

भी अधिक है क्योंकि यह उनके द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी से अपनी शिकायतों के निवारण के लिए मुलाकात करने के कुछ दिनों बाद हुई है। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि 'सब ठीक हैं' और 'हम सभी एक ही राय पर हैं'। तब से, थरूर को कांग्रेस के लिए प्रमुखता से बोलते हुए देखा गया है और उन्होंने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा की शुरुआत भी की थी। पार्टी के एक बयान में कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रचार समिति और घोषणापत्र समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

अलवर में कर्मचारियों ने बजट की कॉपियां जलाई, मांगों की अनदेखी पर जताया विरोध

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा अलवर

जिला मुख्यालय स्थित मिनी सचिवालय गेट पर राज्य सरकार के बजट के विरोध में कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर बजट की कॉपियां जला दीं। कर्मचारियों ने सरकार पर उनकी मांगों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए जोरदार नारेबाजी की और कहा कि अब संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। कर्मचारी नेता मनोज मीणा ने कहा कि इस बार का बजट कर्मचारियों, संविदा कर्मियों, मानदेय कर्मियों और पेंशनरों के लिए पूरी तरह निराशाजनक है। बजट भाषण में कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर केवल तीन मिनट चर्चा की गई और इस दौरान किसी भी पक्ष ने समर्थन नहीं किया, जिससे साफ है कि बजट कर्मचारियों के हित में नहीं है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि पिछले बजट में पदोन्नति संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए कैडर पुनर्गठन की घोषणा की गई थी, लेकिन इस बार न तो पदोन्नति का समाधान हुआ और न ही वेतन विसंगतियों को लेकर कोई ठोस फैसला लिया गया। आठवें वेतन आयोग को लेकर भी केवल समिति बनाने की बात कही गई है। कर्मचारी नेता केसर सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को समझने के बजाय समितियां बनाकर समय निकाल रही है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

अलवर-भरतपुर मार्ग पर अचेत मिले युवक की मौत, इलाज के दौरान तोड़ा दम

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा अलवर

जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र में अलवर-भरतपुर मार्ग पर अचेत अवस्था में मिले 23 वर्षीय युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। युवक ने तबीयत खराब होने की जानकारी पहले अपने दोस्त को फोन पर दी थी, जिसके कुछ देर बाद वह कार में बेहोश मिला। जानकारी के अनुसार नौगांवा निवासी योगेश सैनी (23) पुत्र पांच्याराम सैनी वर्तमान में कठूमर के रामपुरा तसई में रह रहा था। बुधवार शाम करीब 3 बजे वह अपनी स्कॉर्पियो कार लेकर घर से निकला था। करीब 4 बजे उसने एक दोस्त को फोन कर तबीयत खराब होने की सूचना दी। इसके बाद ताजपुर स्थित देवनारायण मंदिर से करीब 100 मीटर दूर अलवर रोड पर वह अपनी गाड़ी में अचेत अवस्था में मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर उसे तुरंत नगर अस्पताल पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे अलवर और फिर जयपुर रेफर कर दिया, लेकिन जयपुर ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार योगेश के पिता का पहले ही निधन हो चुका है। वह नौगांवा से कठूमर आकर वंदना स्कूल के पास खेत खरीदकर मकान का निर्माण करा रहा था। गुरुवार को बड़ौदामेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के दादा मनोहर लाल सैनी ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है, जिसके आधार पर मामले की जांच जारी है।

साउथ अफ्रीका में अलवर निवासी युवक की हार्ट अटैक से मौत

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा अलवर

जिले के राजगढ़ क्षेत्र के धमरेड़ गांव निवासी युवक की साउथ अफ्रीका में हार्ट अटैक से मौत हो गई। युवक छह महीने पहले रोजगार की तलाश में विदेश गया था। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में शोक छा गया और परिजन शव को भारत लाने के लिए सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार धमरेड़ गांव निवासी गंगाराम योगी (37) पुत्र छोटेलाल 15 अगस्त 2025 को साउथ अफ्रीका के लुसाका में खान में मजदूरी करने गया था। उसे अजमेर जिले के किशनगढ़ निवासी एक ठेकेदार कंपनी के खर्च पर वहां लेकर गया था। विदेश में काम करने के दौरान वह हर महीने परिवार को 30 से 35 हजार रुपए भेजता था, लेकिन पिछले दो-तीन महीनों से पैसे नहीं भेजे थे। डीएनटी समाज के अलवर संयोजक पुखराज योगी ने बताया कि बुधवार को अचानक गंगाराम की तबीयत बिगड़ गई। पहले कमर में दर्द हुआ, फिर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार हार्ट अटैक से 30 मिनट में उसकी मौत हो गई। गंगाराम के परिवार में पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा है। परिवार को बताया गया है कि शव आने में करीब 10 दिन लग सकते हैं।

ढहलावास के हरिजन मोहल्ले में जलभराव से परेशानी, ग्रामीणों ने नाली निर्माण की मांग उठाई

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा उमरैण

क्षेत्र के ढहलावास गांव के हरिजन मोहल्ले में जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से कई दिनों से कीचड़ जमा होने की समस्या बनी हुई है। इससे स्थानीय निवासियों, खासकर महिलाओं और बच्चों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द नाली निर्माण कराने की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार मोहल्ले में लगे दो हैंडपंपों का पानी सीधे रास्ते पर बहता है। इसके अलावा कई घरों से निकलने वाला गंदा पानी भी सड़क पर ही जमा हो जाता है। नाली की व्यवस्था नहीं होने के कारण यह पानी लंबे समय तक जमा रहकर कीचड़ में बदल जाता है, जिससे लोगों को रोजमर्रा के कामों में दिक्कतें आती हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कीचड़ के कारण रास्तों पर चलना मुश्किल हो गया है और बच्चों व बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। कई बार लोग फिसलकर गिर भी जाते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मोहल्ले में जल्द से जल्द नाली का निर्माण कराया जाए, ताकि पानी की निकासी सुचारु रूप से हो सके। उनका कहना है कि नाली बनने से पानी नदी की ओर बह जाएगा और जलभराव व कीचड़ की समस्या से स्थायी राहत मिल सकेगी।

अलवर में खुलेगा सेंटर फॉर एक्सीलेंस, लाल प्याज उत्पादक किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा अलवर

लंबे इंतजार के बाद राज्य सरकार ने अलवर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोलने की घोषणा की है। इस फैसले से जिले के लाल प्याज उत्पादक किसानों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। सेंटर की स्थापना से लाल प्याज की फसल पर आधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा और नई-नई उन्नत किस्में विकसित की जा सकेंगी। साथ ही किसानों को प्याज के लंबे समय तक भंडारण की सुविधा मिलेगी, जिससे वे बाजार में बेहतर दाम मिलने पर अपनी उपज बेचकर अधिक मुनाफा कमा सकेंगे। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि जिले की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

अलवर जिला लाल प्याज के उत्पादन में प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी अग्रणी स्थान रखता है। नासिक के बाद अलवर देश की दूसरी सबसे बड़ी प्याज मंडी के रूप में जाना जाता है। फसल के समय यहां से लाल प्याज राजस्थान के विभिन्न जिलों के साथ-साथ देश के कई राज्यों और विदेशों तक भेजा जाता है। जिले में बड़े स्तर पर उत्पादन होने के बावजूद अब तक किसानों को इसका पूरा आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसका प्रमुख कारण अलवर के लाल प्याज में अधिक नमी होना है, जिससे इसे लंबे समय तक सुरक्षित भंडारित करना संभव नहीं हो पाता था।

भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण किसानों को फसल तैयार होते ही जल्दी बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था। कई बार मंडियों में प्याज के दाम कम होने से किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। ऐसी स्थिति में कुछ किसानों को मजबूरी में अपनी उपज कम कीमत पर बेचनी पड़ती थी, जबकि कई बार फसल खराब होने की आशंका के चलते प्याज को नदियों और सड़कों पर फेंकने की नौबत तक आ जाती थी। इस वर्ष भी सीजन की शुरुआत में मंडी में कम दाम मिलने के कारण कई किसानों को अपनी उपज नष्ट करनी पड़ी थी। अब सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना के बाद किसानों को इस समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि कम दाम होने पर वे अपनी फसल का सुरक्षित भंडारण कर सकेंगे।

उद्यान विभाग के सहायक निदेशक केएल मीणा के अनुसार अलवर जिला देश में लाल प्याज की पैदावार में अग्रणी स्थान रखता है। जिले को एक जिला, एक उत्पाद योजना के तहत पंच-गौरव कार्यक्रम में लाल प्याज उत्पादन के लिए विशेष पहचान दी गई है। उन्होंने बताया कि अलवर के लाल प्याज की देश और विदेश में व्यापक मांग है, जिससे किसानों को अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना से प्याज के भंडारण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और विपणन की आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार होगा और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध हो सकेगा।

उन्होंने बताया कि इस केंद्र की स्थापना के बाद जिले के किसान और युवा प्याज सहित अन्य सब्जियों के उत्पादन को लेकर नए अनुसंधान और प्रयोग कर सकेंगे। इससे कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। साथ ही किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने, फसल की गुणवत्ता सुधारने और नुकसान कम करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

अलवर प्याज मंडी संरक्षक अभय सैनी ने बताया कि जिले के लाल प्याज की मांग राजस्थान के अलावा हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में लगातार बनी रहती है। इसके साथ ही अलवर का प्याज विदेशों में भी निर्यात किया जाता है, जिससे जिले की पहचान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई है। उन्होंने बताया कि अलवर के लाल प्याज में तीखापन अधिक होता है, जिसके कारण बड़े होटल, रेस्टोरेंट और खाद्य उद्योगों में इसकी मांग ज्यादा रहती है।

जिले में मालाखेड़ा, उमरैण, रामगढ़, गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़ और अलवर तहसील क्षेत्रों में लाल प्याज का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना से इन क्षेत्रों के किसानों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। आधुनिक तकनीक और बेहतर भंडारण सुविधाओं के माध्यम से किसानों को फसल खराब होने के नुकसान से बचाया जा सकेगा और उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस कृषि क्षेत्र में तकनीकी विकास का महत्वपूर्ण केंद्र साबित होगा। इससे न केवल प्याज उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार होगा, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और जिले की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य सरकार की यह पहल अलवर को कृषि नवाचार और प्याज उत्पादन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

गोविंदगढ़ में दिनदहाड़े गोवंश पर हमला, गंभीर हालत में अलवर रेफर

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा अलवर

जिले के गोविंदगढ़ कस्बे में दिनदहाड़े गोवंश पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। गोविंदगढ़-प्लानखेड़ा मार्ग स्थित निरंकारी भवन के पास जंगल क्षेत्र में गुरुवार सुबह करीब 10 बजे अज्ञात लोगों ने गोवंश को गंभीर रूप से घायल कर दिया। खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने घायल गोवंश को देखा तो मौके पर मौजूद हमलावर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही गोविंदगढ़ थानाधिकारी धर्म सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायल गोवंश को राजकीय पशु चिकित्सालय गोविंदगढ़ पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के दौरान उसके पेट पर गंभीर घाव मिलने पर टांके लगाए गए। हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने उसे बहुउद्देश्यीय पशु चिकित्सालय अलवर रेफर कर दिया। स्थानीय निवासी सुनील कुमार ने बताया कि खेतों में काम कर रहे लोगों ने सबसे पहले गोवंश को घायल अवस्था में देखा और आसपास के लोगों को सूचना दी। लोगों के पहुंचने पर अज्ञात व्यक्ति मौके से भाग निकले। घटना को लेकर क्षेत्र में रोष है। पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष रवि सनातनी ने घटना की निंदा करते हुए प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और संदिग्धों की तलाश जारी है।

मांदला कला में वार्ड पुनर्गठन में गड़बड़ी पर ग्रामीणों का विरोध, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा रामगढ़

पंचायत समिति क्षेत्र के मांदला कला गांव में वार्ड पुनर्गठन में गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे और समस्या के समाधान की मांग की। एसडीएम बाबूलाल वर्मा की अनुपस्थिति में ग्रामीणों ने रीडर जीतू सैनी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि वे लंबे समय से वार्ड नंबर 4 में निवास कर रहे हैं, लेकिन वोटर सूची में त्रुटि के कारण एक ही परिवार के कुछ सदस्यों के नाम वार्ड नंबर 3 और कुछ के वार्ड नंबर 4 में दर्ज कर दिए गए हैं। इससे प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ भविष्य में मतदान के दौरान भी परेशानी की आशंका है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार संबंधित बीएलओ से शिकायत कर अपने वोट सही वार्ड में जोड़ने की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि वर्षों से वार्ड नंबर 4 में रहने के बावजूद उनके नाम गलत वार्ड में दर्ज हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि जिन परिवारों के वोट वार्ड नंबर 3 में दर्ज हैं, उन्हें हटाकर सही वार्ड नंबर 4 में जोड़ा जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या न हो। इस दौरान शब्बीर, मनीष, मजीद, राजू, असमदीन, अजरुद्दीन, रसीद और रेखा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

सात दिन बाद भी खाली हाथ रेस्क्यू टीम: ओडेला खनन हादसे में चालक का सुराग नहीं, पानी से भरी खाई बनी बड़ी चुनौती

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा अलवर

जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के ओडेला गांव स्थित खनन क्षेत्र में हुए दर्दनाक हादसे के सात दिन बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू टीम को कोई ठोस सफलता नहीं मिल सकी है। पोकलेन मशीन चालक रामानंद अब तक लापता है, जिससे प्रशासन की कोशिशों पर सवाल उठने लगे हैं और परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। हादसे के बाद से प्रशासनिक अमला लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है, लेकिन पानी से भरी गहरी खाई रेस्क्यू अभियान में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। खदान में भरे पानी को निकालने के लिए पहले छोटे पंपों से करीब दो फीट पानी निकाला गया, लेकिन इससे कोई खास राहत नहीं मिली। बाद में भीलवाड़ा से मंगाए गए 250 एचपी क्षमता के बड़े वाटर पंप से करीब 10 फीट पानी निकालकर आसपास के खेतों में छोड़ा गया, जिससे खेत पानी से लबालब भर गए और हालात और जटिल हो गए। गुरुवार दोपहर अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीना महावर और ग्रामीण एडिशनल एसपी प्रियंका सिंह मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू कार्यों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने एसडीएम बाबूलाल वर्मा, डीएसपी पिंटू कुमार तथा एनडीआरएफ-एसडीआरएफ टीम के साथ खदान में उतरकर स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। हालांकि लगातार निगरानी के बावजूद अब तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। रेस्क्यू अभियान के दौरान बुधवार को पानी में तैरता हुआ चालक रामानंद का जूता मिला, जबकि पोकलेन मशीन से उसका कंबल बरामद हुआ। इन वस्तुओं के मिलने के बाद परिजनों की आशंका और गहरा गई है। चालक के परिजन पिछले सात दिनों से खदान मार्ग पर ही डेरा डाले हुए हैं। उनका कहना है कि प्रशासन प्रयास तो कर रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस सफलता नहीं मिलने से उनकी उम्मीदें कमजोर पड़ रही हैं। दरअसल खनन के दौरान अचानक पहाड़ का हिस्सा दरकने से पोकलेन मशीन सहित चालक करीब 150 फुट गहरी पानी से भरी खाई में समा गया था। खाई में पानी की गहराई और मात्रा का सही अनुमान अब तक नहीं लग सका है। एनडीआरएफ की टीम आधुनिक कैमरों और उपकरणों से पानी के भीतर तलाश कर रही है, लेकिन अभियान को अभी तक सफलता नहीं मिली है। सात दिन बीतने के बावजूद रेस्क्यू अभियान के नतीजे सामने नहीं आने से प्रशासन की चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। परिजनों की बेचैनी के बीच प्रशासन का दावा है कि चालक का पता चलने तक अभियान जारी रहेगा, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उम्मीदें कमजोर होती नजर आ रही हैं।

रामगढ़ में किसानों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, तीन मांगों को लेकर उठाई आवाज

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा रामगढ़

क्षेत्र में किसानों और ग्रामीणों ने गुरुवार को एसडीएम बाबूलाल वर्मा को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर किसानों से जुड़े तीन प्रमुख मुद्दों पर केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। ज्ञापन में भारत-अमेरिका ट्रेड डील की समीक्षा, अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और यूजीसी से जुड़े प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने की मांग उठाई गई। किसानों ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते से भारतीय कृषि क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। उनका कहना है कि यदि विदेशी कृषि उत्पाद सस्ते दामों पर बाजार में आए तो स्थानीय किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलेगा, जिससे छोटे और सीमांत किसानों पर आर्थिक संकट गहरा सकता है। किसानों ने सरकार से अन्नदाताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। ज्ञापन में अरावली पर्वतमाला के संरक्षण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। किसानों का कहना है कि अरावली पर्यावरण संतुलन, वर्षा चक्र और भूजल स्तर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने अरावली क्षेत्र में खनन और अवैध गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की। इसके साथ ही उच्च शिक्षा में समान अवसर और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए यूजीसी से जुड़े प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग भी की गई। इस दौरान पूर्व सरपंच कमल जाटव, राजाराम, फ़ख़रुद्दीन, हरिराम, दिन मोहम्मद सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।

अलवर में बोरिंग खुदाई के दौरान चमकदार वस्तु मिलने से अफरातफरी, जांच में जुटा प्रशासन

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा अलवर

शहर की अलकापुरी कॉलोनी में जलदाय विभाग की बोरिंग खुदाई के दौरान चांदी जैसी चमकदार वस्तु निकलने की सूचना से गुरुवार को अफरातफरी मच गई। सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और बोरिंग से निकलने वाली कीचड़ व मिट्टी में से चमकदार पत्थर जैसी वस्तु उठाने लगे। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार जलदाय विभाग की ओर से पानी की समस्या को देखते हुए कॉलोनी में दो दिन पहले बोरिंग खुदाई का कार्य शुरू किया गया था। गुरुवार सुबह खुदाई के दौरान अचानक चांदी जैसी चमकदार वस्तु नजर आने लगी, जिसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। लोगों में इस वस्तु को लेने की होड़ मच गई और कई लोग कीचड़ में उतरकर उसे इकट्ठा करते नजर आए। स्थानीय दुकानदारों ने मामले की सूचना पार्षद व प्रशासन को दी। प्रशासन ने मौके की जानकारी लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि चमकदार दिखने वाली वस्तु क्या है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चांदी मिलने की खबर से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। जांच के बाद ही वस्तु की वास्तविकता सामने आएगी। वहीं घटना के वायरल वीडियो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बने हुए हैं।

मंडी मोड़ के पास ट्रक ड्राइवर ने जहरीला पदार्थ खाया, इलाज के दौरान मौत

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा अलवर

शहर के एनईबी थाना क्षेत्र अंतर्गत मंडी मोड़ के समीप एक ट्रक ड्राइवर द्वारा जहरीला पदार्थ सेवन करने का मामला सामने आया है। हालत बिगड़ने पर उपचार के दौरान जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ट्रक चालक ने जहरीला पदार्थ खाने के बाद अपने घर बकतल की चौकी पहुंचकर परिजनों को घबराहट होने की बात बताई। उसकी हालत बिगड़ती देख परिजन उसे तुरंत अलवर शहर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। स्थिति गंभीर होने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान मुख्तियार सिंह पुत्र तारा सिंह निवासी बकतल की चौकी के रूप में हुई है, जो लंबे समय से मंडी मोड़ क्षेत्र में ट्रक चालक का कार्य कर रहा था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के अनुसार शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। फिलहाल जहरीला पदार्थ सेवन के कारणों की जांच की जा रही है और परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

रोहटरू 108 एंबुलेंस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, चार घायल

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा रोहट

थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे-62 पर रेडियो नदी के पास 108 एंबुलेंस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में एंबुलेंस में सवार चार लोग घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद रोहट के टैक्सी चालक गोविंद भाई ने मानवता का परिचय देते हुए अन्य लोगों की मदद से घायलों को निजी वाहनों से रोहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल मरीजों को जोधपुर रेफर किया गया।घटना की सूचना मिलते ही पुलिस थाना रोहट से एएसआई मोडाराम मय जाब्ता मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।वहीं रोहट सामूदाय स्वास्थ केन्द्र पर घायलों का उपचार कर जोधपुर रैफर किया गया। जानकारी अनुसार पाली बांगड अस्पताल से मरीज को 108 की मदद से जोधपुर रैफर किया गया। जहां रोहट केनिकट निर्माणधीन बाईपास पर लगे डाईवर्जन पर 108 एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर टकरा गई।गनीमत रहीं की राहगीरों की मदद से 108 में सवार घायलों को समय पर उपचार मिल गया। हादसे में एंबुलेंस चालक व ईएमटी को भी गंभीर चौटे पहुंची।

भूराराम देवासी हत्याकांड: 72 घंटे बाद प्रशासन-ग्रामीणों में बनी सहमति, धरना समाप्त

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा बाली

उपखंड क्षेत्र के सेवाड़ी गांव में हुए भूराराम देवासी हत्याकांड को लेकर चार दिनों से चल रहा गतिरोध आखिरकार समाप्त हो गया। गुरुवार देर रात प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच दूसरे दौर की वार्ता सफल रही, जिसके बाद सेवाड़ी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर जारी धरना-प्रदर्शन खत्म कर दिया गया। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व सेवाड़ी गांव के पास एक कुएं में भूराराम देवासी का शव मिला था। परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर शव लेने से इंकार कर दिया था। मामले ने तूल पकड़ा तो गांव सहित आसपास के क्षेत्रों के लोग भी धरने में शामिल हो गए।

प्रमुख मांगों पर बनी सहमति

मृतक के परिजनों और ग्रामीणों द्वारा रखी गई प्रमुख मांगों में–
प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी का गठन,
मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम,
नामजद आरोपी को हिरासत में लेना,
धरने में शामिल किसी भी व्यक्ति के

खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करना शामिल थीं। प्रशासन ने इन सभी मांगों पर सहमति जताते हुए निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिलाया। अब मामले की जांच बाली पुलिस के स्थान पर सोजत वृत्ताधिकारी (सीओ) रतन देवासी द्वारा की जाएगी। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। दूसरे दौर की वार्ता में बनी बात पहला दौर अस्पताल में हुआ था, लेकिन उसमें सहमति नहीं बन सकी थी। दूसरे दौर की वार्ता में पुलिस उपाधीक्षक पारसराम चौधरी, सोजत वृत्ताधिकारी रतन देवासी, बाली एसडीएम दिनेश विश्नोई, राष्ट्रीय पशुपालक संघ अध्यक्ष लालसिंह देवासी, डीएनटी समाज प्रदेश सचिव रतन कालबेलिया, कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिशुपाल सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष यशपाल सिंह, ओबीसी मोर्चा प्रदेश मंत्री मोहनलाल देवासी, पूर्व सरपंच नागेश देवासी, मुंडारा मंडल अध्यक्ष साकलाराम देवासी, शंकरलाल कोलीवाड़ा, झालाराम देवासी, पूर्व सरपंच लूणावा मोहनलाल चौधरी, सेसली सरपंच जगदीश चौधरी, सवाराम, भंवराराम/भगाराम देवासी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मृतक के बेटे धनपत भी वार्ता में शामिल हुए। करीब 72 घंटे चले गतिरोध के बाद बनी सहमति से क्षेत्र में तनाव कम हुआ है। प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जनप्रतिनिधि व अधिकारी वार्ता करते हुए।

जोधपुर फाटक लाईन को बाईपास से या अतिरिक्त अंडरब्रिज की मांग का हस्ताक्षर अभियान शुरू

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा मारवाड़ जंक्शन

जोधपुर रेलवे फाटक लाईन को बाईपास से लिए जाने या फाटक के पास ओवरब्रिज के अलावा अतिरिक्त अंडरब्रिज दिए जाने की मांग को लेकर जय श्री कृष्णा साई दर्शन हेल्पलाईन ग्रुप मारवाड़ जंक्शन ने किया हस्ताक्षर अभियान शुरू। कोई भी योजना शुरू होने से पहले प्रयास किया जाए तो हर काम संभव होते हैं। इसके लिए आंदोलन की जरूरत नहीं होती है , हमें सिर्फ पाली के सांसद श्रीपीपी चौधरी जी के लगातार संपर्क में रहना हैं। विश्वस्त्र सूत्रों का कहना है कि यह केंद्र से जुड़ा मामला हैं, इसलिए सांसद साहब से लगातार मांग की जानी जरूरी हैं। सोजत रोड में रेलवे स्टेशन के पास फाटक संख्या 53 पर फाटक बंद करने से पहले ओवरब्रिज दिया गया था परंतु पाली सांसद श्री पीपी चौधरी जी की पहल के बाद 6 करोड़ का अंडरब्रिज भी बंद की गई 53 नंबर फाटक के नीचे ही दिया गया है जिसका कार्य भी शुरू होने वाला है।

सरस्वती शिक्षा विद्यालय गिराली का वार्षिकोत्सव व भामाशाह सम्मान आयोजित हुआ

कक्षा आठवीं बोर्ड के विद्यार्थियों को दी विदाई

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा रानी

निकटवर्ती ग्राम गिराली के सरस्वती शिक्षा निकेतन राजकीय प्राथमिक विद्यालय का वार्षिकोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया द्य समारोह के मुख्य अतिथि समाजसेवी सुरेंद्र सिंह सोलंकी वारा सोलंकिया विशेष अतिथि अर्जुन कुमार चौहान माता जी वाड़ा एवं मदन सिंह चौहान गुड़ा मांगलियान समारोह की अध्यक्षता विद्यालय के संस्था प्रधान भैराराम ने की अतिथियों ने शिक्षा पर जोर देते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की ! इस मौके पर कक्षा आठवीं के विद्यार्थियों श्रीफल एवं तिलक लगाकर विदाई दी गई संस्था की ओर से अतिथियों एवं भामाशाह का साफा एवं माला से बहुमान किया गया !इस मौके पर बालिका द्वारा कई संस्कृति कार्यक्रम प्रस्तुत किए ! इस अवसर पर भामाशाह नारायण लाल भोपाजी, कानाराम, रूपाराम, मदनलाल, विद्यालय के दिलीप कुमार दरिया,अशोक धवल,सुरेश कुमार,गोपाल कृष्ण मालवीय आदि उपस्थित थे !

युवा शक्ति को आत्मनिर्भरता की नई उड़ान देता राजस्थान का बजटः विधायक दीप्ति

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा राजसमंद

विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कहा कि राजस्थान सरकार का बजट प्रदेश की युवा शक्ति को सशक्तए सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने की दूरदर्शी पहल है। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित कर उन्हें रोजगार मांगने वाले से रोजगार देने वाला बनाने का स्पष्ट विजन प्रस्तुत करता है। माहेश्वरी ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक के ऋण पर 100 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध कराने के लिए 1 हजार करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। यह निर्णय प्रदेश में स्टार्टअप संस्कृति और लघु उद्योगों को गति देगा। साथ ही नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में ऋण सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ किए जाने तथा लखपति दीदी योजना में ऋण सीमा वृद्धि से ग्रामीण एवं महिला उद्यमियों को नई आर्थिक शक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा और कौशल विकास को बजट में विशेष प्राथमिकता दी गई है। 400 विद्यालयों को उन्नत कर उत्कृष्टता मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए 1 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है

पीएम श्री विद्यालय निम्बज में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय वार्ता

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा आबूरोड

रेवदर तहसील के निम्बज स्थित पीएम श्री विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र-छात्राओं को साइबर सुरक्षा और कंप्यूटर शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना था। वार्ता में विशेषज्ञों ने बदलते डिजिटल दौर में सावधानी और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता पर जोर दिया।

अंतरराष्ट्रीय वक्ता के रूप में माधव विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. भावेश कुमावत ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। डाटा चोरी, ओटीपी लीक तथा डिजिटल गिरफ्तारी जैसी घटनाओं से आमजन को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है। उन्होंने विद्यार्थियों को सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, गोपनीय जानकारी की रक्षा तथा ऑनलाइन ठगी से बचाव के विभिन्न उपाय बताए। साथ ही कई उपयोगी तकनीकों की जानकारी देकर उन्हें सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय वक्ता के रूप में माधव विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. गीतम सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि आधुनिक शिक्षा में कंप्यूटर का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। कंप्यूटर दक्षता के बिना गुणवत्तापूर्ण अध्ययन, ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग, कौशल विकास तथा रोजगार के अवसरों तक पहुँचना कठिन है। उन्होंने विद्यार्थियों को तकनीकी रूप से सक्षम बनने का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

आर्थिक सर्वेक्षण और वित्त विधेयक पर आईसीएआई शाखा द्वारा सेमिनार का आयोजन

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा राजसमन्द

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के स्थानिय शाखा द्वारा मंगलवार को आर्थिक सर्वेक्षण 2026 एवं वित्त विधेयक 2026 के प्रमुख प्रावधानों पर केंद्रित व्यावसायिक सेमिनार आयोजित हुआ। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कर पेशेवरों को देश में हो रहे नवीन आर्थिक बदलावों और कर संबंधी जटिल संशोधनों से गहराई से अवगत कराना था, ताकि वे अपने व्यावसायिक ज्ञान और कार्यक्षमता को और अधिक सुदृढ़ कर सकें। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि आगामी बजट और आर्थिक नीतियां भारत को एक पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित कर प्रशासन की ओर ले जा रही हैं। शाखा चेयरमैन सीए दिनेश चन्द्र सनाढ्य ने स्वागत उद्बोधन में सेमिनार की प्रासंगिकता पर कहा कि वित्त विधेयक के माध्यम से प्रस्तावित किए गए संशोधन केवल कानूनी बदलाव नहीं हैं, बल्कि ये इस बात का प्रतीक हैं कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर कानून अब अपने एक अत्यंत परिपक्व चरण में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने विशेष रूप से जीएसटी अपीलीय अधिकरण की स्थापना को एक ऐतिहासिक और बहुप्रतीक्षित सुधार बताया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस अधिकरण के शुरू होने से कर-विवादों का समाधान विशेषज्ञता के साथ और त्वरित गति से होगा, जिससे देश के उच्च न्यायालयों पर बढ़ते मुकदमों का बोझ काफी कम हो जाएगा। मुख्य अतिथि एवं रीजनल काउंसिल सदस्य सीए धवल कोठारी ने भी अपने विचार साझा किए और

उपस्थित सदस्यों से पेशेवर प्रतिबद्धताओं को मजबूत करने के साथ-साथ वेलफेयर फंड में अपनी क्षमतानुसार अधिकाधिक योगदान करने का आह्वान किया। सेमिनार को दो विस्तृत तकनीकी सत्रों में विभाजित किया गया था, जिसमें विषय विशेषज्ञों ने गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया। प्रथम सत्र में जयपुर से आए मुख्य वक्ता सीए राहुल लखावनी ने अप्रत्यक्ष कर और जीएसटी अपीलीय अधिकरण की बारीकियों को समझाया। उन्होंने कहा कि अधिकरण की स्थापना से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका अब केवल अनुपालन तक सीमित नहीं रही है, बल्कि अब उनके लिए गुणवत्तापूर्ण प्रतिनिधित्व और रणनीतिक परामर्श के नए द्वार खुल गए हैं। प्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्तावों पर हुआ व्याख्यान दूसरे सत्र में जयपुर के ही विशेषज्ञ सीए विकास गुप्ता ने प्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्तावों पर अपना व्याख्यान दिया। उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि व्यक्तिगत करदाताओं के लिए बनाई गई सरल कर व्यवस्था और स्टार्टअप्स व डैडम् क्षेत्र के लिए दिए गए विशेष प्रोत्साहन देश की आर्थिक विकास दर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।

बड़ा भाणुजा में 679 वर्ष पुराने लक्ष्मीनारायण मंदिर के जीर्णोद्धार का 12 दिवसीय महोत्सव संपन्न

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा राजसमंद

जिले में नाथद्वारा तहसील की खमनोर पंचायत समिति के बड़ा भानुजा गांव में स्थित भगवान श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर के जीर्णोद्धार का 12 दिवसीय महोत्सव हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। पालीवाल ब्राह्मण समाज 44 श्रेणी के प्रमुख टिकायत गांव में स्थित इस प्राचीन मंदिर का निर्माण सन 1347 में समाज के अग्रज राजलजी द्वारा कराया गया था। करीब सात सदियों पुराने इस आस्था के केंद्र के पुनरुद्धार पर आयोजित महोत्सव में भक्ति, शक्ति और सेवा का त्रिवेणी संगम देखने को मिला। आयोजन का शुभारंभ महान संत ज्ञानानंद महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भगवद् गीता कथा के साथ हुआ। 12 दिनों तक चले इस महोत्सव में प्रतिदिन विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों की धूम रही। कथा के साथ-साथ भव्य रामलीला का मंचन किया गया, जिसने दर्शकों को त्रेतायुग की याद दिला दी। इसके पश्चात कथावाचक जुगल किशोर बागोरा द्वारा नानी बाई का मायरा की हृदयस्पर्शी कथा सुनाई गई, जिसे सुनकर भक्त भाव-विभोर हो गए। भगवान कृष्ण की रासलीला के जीवंत मंचन ने पंडाल में गोकुल सा दृश्य उपस्थित कर दिया। महोत्सव के दौरान प्रतिदिन बड़ा भानुजा लक्ष्मीनारायण भक्त मंडल द्वारा भजनों की अमृत वर्षा की गई। पूरे 12 दिनों तक मंदिर में सुबह से लेकर देर रात तक दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने न केवल ठाकुर जी के दिव्य दर्शन किए, बल्कि कथा श्रवण और महाप्रसाद

का लाभ लिया। भोजन और दर्शन की सुव्यवस्थित व्यवस्था समस्त पालीवाल 44 श्रेणी ब्राह्मण समाज बड़ा भानुजा द्वारा की गई, जिसकी आगंतुकों ने सराहना की। महोत्सव के समापन और ध्वजा रोहण के अवसर पर धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र की कई दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की। यह पूरा भव्य आयोजन पालीवाल ब्राह्मण समाज 44 श्रेणी संस्था मेवाड़ के अध्यक्ष शंकरलाल पुरोहित और सुप्रसिद्ध उद्योगपति व समाजसेवी चंद्रशेखर पुत्र जमना लाल पुरोहित के सानिध्य में संपन्न हुआ। शिखर पर नवीन ध्वजा चढ़ाने के साथ ही 12 दिवसीय इस आध्यात्मिक अनुष्ठान का पूर्णाहूति के साथ समापन हुआ। ग्रामीणों के अनुसार इस आयोजन ने न केवल क्षेत्र में धार्मिक चेतना जागृत की है, बल्कि समाज की एकता और प्राचीन विरासत के संरक्षण का संदेश भी दिया है।

विज्ञान एवं गणित के शिक्षकों का तीन दिवसीय स्टेम प्रशिक्षण शिविर संपन्न

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा रानी

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रानी के तत्वावधान में कक्षा 6 से 10 तक में अध्ययन कराने वाले शिक्षकों का तीन दिवसीय स्टेम प्रशिक्षण मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुमेर सिंह सोनीगरा केसानिध्य में सम्पन्न हुआ।आरपी ताज मोहम्मद पठान ने बताया कि इस प्रशिक्षण में कुल 35 शिक्षकों ने दिनांक 10-02-2026 से 12-02-2026 तक प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के प्रथम दिन रजिस्ट्रेशन के बाद पूर्व परख का आयोजन किया गया एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा की गई, गणित एवं विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य पर चर्चा की गई, मिस्ट्री बॉक्स से कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने पर चर्चा की गयी, प्रशिक्षण के द्वितीय दिवस योग,व्यवकलन, गुणन,भाग को किट के माध्यम से समझाया गया,विधुत परिपथ,मानव श्वसन तंत्र,क्षेत्रफल, परिमाप एवं आयतन पर विस्तृत चर्चा की गयी,प्रशिक्षण के तृतीय दिन वक्रिय आकृति,सूत्र निर्माण एवं पदार्थों की प्रकृति पर चर्चा की गई एवं पश्च परख का आयोजन किया गया। अंत में सभी संभागियो से प्रशिक्षण का फ़ीड बैग लिया गया। समापन के अवसर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुमेर सिंह सोनीगरा,अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नैनाराम,प्रधानाचार्य संतोष कुमार राजपुरोहित,आरपी ताज मोहम्मद पठान,मास्टर ट्रेनर्स राहुल आसेरी,भरत कुमार, अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन से सन्दर्भ व्यक्ति अख्तर हुसैन,मुकेश वर्मा,मनीष कुमार शर्मा सहित विभिन्न राजकीय विद्यालयों के सभागी शिक्षक उपस्थित रहे।

देश की आजादी के बाद सोजत विधायक ने किया सुरायता सड़क का सपना पूरा

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा मारवाड़ जंक्शन

देश की आजादी के 79 वर्ष बीत जाने के बाद सोजत की लोकप्रिय विधायक शोभा चौहान द्वारा कई वर्षों से व्यक्तिगत रुचि लिए जाने के बाद जाडन से सुरायता के चार किलोमीटर कच्चे मार्ग को पक्के मार्ग के रूप में तब्दील किए जाने को लेकर राजस्थान सरकार के बजट में 2 करोड़ 20 लाख रुपए की स्वीकृति दिलाने पर संपूर्ण क्षेत्र में खुशी की लहर छा गई हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरायता के प्रधानाचार्य देवेंद्रसिंह मीणा के नेतृत्व में आतिशबाजी कर विधायक का आभार व्यक्त किया। ज्ञात रहे कि जाडन से सुरायता जाने वाले कच्चे मार्ग से अनेक ग्राम पंचायतों से जुड़े सैकड़ो ग्रामों के हजारों ग्रामीणों को रोजाना आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था , विशेषकर वर्षा के समय आवागमन अवरुद्ध हो जाता था परंतु जिला मुख्यालय पाली की एकमात्र सड़क जो कि पाली एवं जोधपुर के मार्गों को जोड़ती है एवं विशेषकर व्यावसायिक दृष्टिकोण, मरीजों के लिए चिकित्सा सुविधाओं, युवक युवतियों के लिए शैक्षिक शिक्षण संस्थाओं से जोड़ने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था परंतु अब सोजत विधायक शोभा चौहान द्वारा व्यक्तिगत रुचि लेकर देश की आजादी के बाद का इतिहास रच दिया गया है। जाडन से सुरायता तक लगभग 10 किलोमीटर की सड़क है

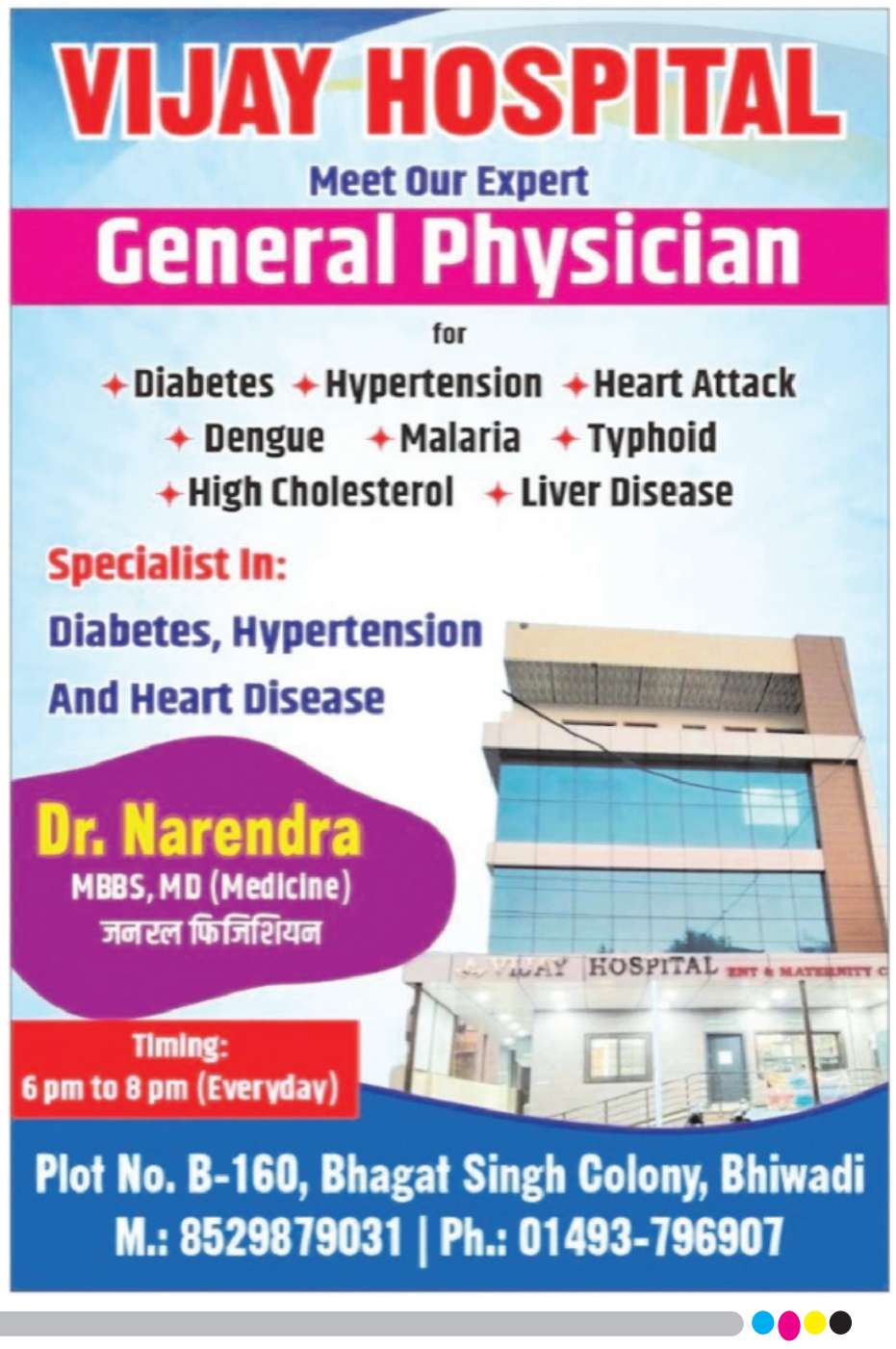

डिजिटल क्रांति पर साइबर प्रहार गंभीर चुनौती

ललित गर्ग

डिजिटल व्यवस्था की मूल आत्मा 'विश्वास' है। जब कोई व्यक्ति मोबाइल स्क्रीन पर उभरे एक क्यूआर कोड को स्कैन करता है या किसी लिंक पर क्लिक करता है, तो वह केवल तकनीक पर ही नहीं, बल्कि उस संपूर्ण तंत्र पर भरोसा करता है जो उसे सुरक्षित लेन-देन का आश्वासन देता है। किंतु जब यही विश्वास ठगी, फर्जी कॉल, फिशिंग, निवेश घोटालों और पहचान चोरी के कारण टूटने लगता है, तब डिजिटल विकास की पूरी अवधारणा कमजोर पड़ने लगती है।

डिजिटल युग ने भारत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन को अभूतपूर्व गति प्रदान की है। मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, ई-कॉमर्स और ऑनलाइन सेवाओं ने लेन-देन को सरल, त्वरित और पारदर्शी बनाया है। आज एक सामान्य नागरिक भी कुछ सेकंड में देश के किसी भी कोने में धन भेज सकता है, बिल जमा कर सकता है या निवेश कर सकता है। यही डिजिटल क्रांति नए भारत और विकसित भारत की आधारशिला मानी जा रही है। किंतु इसी क्रांति के साथ एक गहरी विडंबना भी उभरकर सामने आई है-डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर लूट की भयावह बढ़ोतरी। हजारों करोड़ रुपये की ऑनलाइन ठगी की घटनाएँ न केवल आमजन को आर्थिक रूप से आहत कर रही हैं, बल्कि देश की आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचि लगा रही हैं।

डिजिटल व्यवस्था की मूल आत्मा 'विश्वास' है। जब कोई व्यक्ति मोबाइल स्क्रीन पर उभरे एक क्यूआर कोड को स्कैन करता है या किसी लिंक पर क्लिक करता है, तो वह केवल तकनीक पर ही नहीं, बल्कि उस संपूर्ण तंत्र पर भरोसा करता है जो उसे सुरक्षित लेन-देन का आश्वासन देता है। किंतु जब यही विश्वास ठगी, फर्जी कॉल, फिशिंग, निवेश घोटालों और पहचान चोरी के कारण टूटने लगता है, तब डिजिटल विकास की पूरी अवधारणा कमजोर पड़ने लगती है। यदि बैंकिंग व्यवस्था में नकली नोटों की भरमार हो जाए तो मुद्रा पर विश्वास डगमगा जाता है, उसी प्रकार यदि डिजिटल लेन-देन में ठगी सामान्य अनुभव बन जाए, तो नागरिक डिजिटल माध्यमों से दूरी बनाने लगते हैं। यह स्थिति केवल व्यक्तिगत हानि का प्रश्न नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक ढांचे के लिए भी खतरे की घंटी है। परंपरागत अपराधों और डिजिटल अपराधों की तुलना करें तो दोनों के स्वरूप और प्रभाव में महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है। पहले चोरी या डकैती किसी सीमित भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होती थी, अपराधी की पहचान अपेक्षाकृत स्पष्ट होती थी और जांच प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर संचालित होती थी। डिजिटल अपराधों में अपराधी अदृश्य है, वह किसी दूसरे राज्य या देश में बैठकर वारदात कर सकता है, और कुछ मिनटों में सैकड़ों लोगों को निशाना बना सकता है। पारंपरिक अपराध में जोखिम अपराधी के लिए अधिक था, डिजिटल अपराध में जोखिम कम और लाभ अधिक है। यही असंतुलन इसे अत्यंत खतरनाक बनाता है।

एक अन्य तुलनात्मक पक्ष यह है कि डिजिटल अपराधों में पीड़ित की मनोवैज्ञानिक स्थिति भी अलग होती है। ठगी का

शिकार व्यक्ति स्वयं को अपराधी के सामने असहाय पाता है। पुलिस और साइबर क्राइम कार्यालयों के चक्कर लगाने के बाद भी जब उसे तकनीकी कारणों का हवाला देकर लौटा दिया जाता है, तो उसके भीतर व्यवस्था के प्रति गहरा अविश्वास जन्म लेता है। कई मामलों में यह देखा गया है कि शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया जटिल है, समुचित मार्गदर्शन नहीं मिलता, और समय पर कार्रवाई न होने से धन की रिकवरी असंभव हो जाती है। इससे यह धारणा बनती है कि डिजिटल अपराध का कोई वास्तविक दंड नहीं है। सरकार और न्यायपालिका ने समय-समय पर इस समस्या की गंभीरता को स्वीकार किया है। शीर्ष अदालत द्वारा ऑनलाइन धोखाधड़ी को आर्थिक सुरक्षा से जोड़कर देखना इस बात का संकेत है कि यह केवल व्यक्तिगत अपराध नहीं, बल्कि संगठित आर्थिक आक्रमण भी हो सकता है। किंतु नीति-निर्माण और क्रियान्वयन के बीच की दूरी अभी भी बनी हुई है। अनेक प्लेटफार्म और हेल्पलाइन स्थापित किए गए हैं, परंतु उनकी कार्यप्रणाली में त्वरित प्रतिक्रिया, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की कमी स्पष्ट दिखती है। यदि शिकायत के बाद प्रारंभिक 'गोल्डन ऑवर' में ही बैंक खाते फ्रीज करने और ट्रांजैक्शन ट्रैक करने की प्रभावी व्यवस्था न हो, तो बाद की प्रक्रिया औपचारिकता बनकर रह जाती है।

वित्तीय प्रणाली की दृष्टि से देखें तो डिजिटल धोखाधड़ी का बढ़ना निवेश, उपभोग और बैंकिंग व्यवहार पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यदि आमजन को यह आशंका सताने लगे कि ऑनलाइन निवेश योजनाएँ या भुगतान सुरक्षित नहीं हैं, तो वह नकद लेन-देन की ओर लौट सकता है। यह प्रवृत्ति सरकार की कैशलेस अर्थव्यवस्था की नीति को कमजोर करेगी। इसके अतिरिक्त, विदेशी निवेशकों के लिए भी यह संकेत नकारात्मक हो सकता है कि साइबर सुरक्षा का ढांचा पर्याप्त सुदृढ़ नहीं है। अतः यह केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि आर्थिक नीति का भी केंद्रीय प्रश्न है। समाधान के स्तर पर तुलनात्मक रूप से देखें तो विकसित देशों ने साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में रखा है। वहाँ विशेषीकृत एजेंसियाँ, उच्च प्रशिक्षित तकनीकी विशेषज्ञ, त्वरित डेटा साझा करने की प्रणाली और सख्त दंडात्मक प्रावधान हैं। भारत में भी साइबर क्राइम ब्यूरो और डिजिटल सुरक्षा तंत्र मौजूद हैं, परंतु उनकी क्षमता, संसाधन और प्रशिक्षण को और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। स्थानीय पुलिस बल को केवल पारंपरिक अपराधों की नहीं, बल्कि डिजिटल फॉरेंसिक, ब्लॉकचेन ट्रैकिंग और डेटा विश्लेषण की भी विशेषज्ञता दी जानी चाहिए। जब तक जांच एजेंसियाँ तकनीकी रूप से अपराधियों से एक कदम आगे नहीं होंगी, तब तक रोकथाम कठिन रहेगी।

एक महत्वपूर्ण पक्ष नागरिक जागरूकता का भी है। तकनीक जितनी उन्नत होती है, अपराधी भी उतने ही नए तरीके अपनाते हैं। अतः केवल सरकारी तंत्र पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। विद्यालयों, महाविद्यालयों और सामाजिक संगठनों के माध्यम से डिजिटल साक्षरता अभियान चलाना आवश्यक है, ताकि लोग संदिग्ध लिंक, कॉल और निवेश प्रस्तावों से सावधान रहें। किंतु यह भी ध्यान रखना होगा कि जागरूकता का दायित्व पीड़ित पर डालकर व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती। सुरक्षा का मूल दायित्व तंत्र का है, नागरिक का नहीं। भ्रष्टाचार और लापरवाही भी इस समस्या को जटिल बनाते हैं। यदि बैंक या भुगतान प्लेटफार्म समय पर कार्रवाई नहीं करते, या आंतरिक मिलीभगत से फर्जी खाते संचालित होते हैं, तो यह केवल तकनीकी त्रुटि नहीं, बल्कि संस्थागत विफलता है। इसलिए पारदर्शी ऑडिट प्रणाली, जवाबदेही और कठोर दंड अनिवार्य हैं। डिजिटल प्लेटफार्मों की केवाईसी प्रक्रिया को अधिक कठोर और वास्तविक बनाना होगा, ताकि फर्जी पहचान के माध्यम से खाते खोलना कठिन हो।

अंततः डिजिटल क्रांति का उद्देश्य सुविधा, पारदर्शिता और समृद्धि है। यदि यही क्रांति भय, असुरक्षा और अविश्वास का कारण बनने लगे, तो उसका नैतिक औचित्य कमजोर पड़ जाएगा। भारत जैसे विशाल देश में डिजिटल परिवर्तन को रोकना संभव नहीं, और न ही यह वांछनीय है। किंतु इसे सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना अनिवार्य है। सरकार को नीति, तकनीक और प्रशासन-तीनों स्तरों पर समन्वित रणनीति अपनानी होगी। साइबर अपराध के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई, पीड़ितों को समयबद्ध राहत, जांच एजेंसियों का सशक्तीकरण और वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही-ये सब मिलकर ही धोखाधड़ी मुक्त डिजिटल परिवेश का निर्माण कर सकते हैं। डिजिटल भारत की सफलता केवल ऐप्स और आंकड़ों से नहीं, बल्कि उस विश्वास से मापी जाएगी जो नागरिक अपने मोबाइल स्क्रीन पर उभरते हर ट्रांजैक्शन संदेश के साथ महसूस करता है। यदि यह विश्वास सुरक्षित रहा, तो डिजिटल क्रांति राष्ट्र को नई ऊँचाइयों पर ले जाएगीय यदि यह टूट गया, तो समृद्धि का सपना भी अधूरा रह जाएगा। अतः समय की मांग है कि डिजिटल धोखाधड़ी को एक राष्ट्रीय चुनौती मानकर उसके समाधान की दिशा में ठोस, निर्णायक और पारदर्शी कदम उठाए जाएँ, ताकि विकसित भारत की आधारशिला मजबूत और अडिग रह सके।

संपादकीय

फर्जी की मर्जी पर अंकुश

डीपफेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से झूठ को सच बनाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर केंद्र सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। इस तरह के भ्रमित करने वाली सामग्री प्रसारित करने वाले सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाले नियमों को सख्त बनाया जा रहा है। जिससे डिजिटल कंपनियों और प्लेटफॉर्मों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, खासकर डीपफेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई से निर्मित सामग्री के संबंध में। दरअसल, ये नवीनतम बदलाव उन शिकायतों के बाद किए गए हैं जिसमें एआई बॉट द्वारा पथभ्रष्ट करने वाली उत्तेजक छवियों के निर्माण करने के आरोप लगे हैं। जिसके खिलाफ दुनिया के कई देशों ने भी सख्त कदम उठाए हैं। उल्लेखनीय है कि आईटी के नये नियम बीस फरवरी से लागू होंगे। इसके बाद एआई के जरिये निर्मित सामग्री पर इस बात का लेबल लगाना जरूरी होगा कि उसे कृत्रिम रूप से गढ़ा गया है। साथ ही प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को उपयोगकताओं को भरोसा दिलाना होगा कि साझा की जा रही सामग्री एआई द्वारा निर्मित है या नहीं। ऐसे वक्त में जब लोगों की संवेदनाओं और भरोसे से खिलवाड़ का खेल द्रुत गति से जारी है, केंद्र सरकार की ओर से उठाया गया यह जरूरी कदम कहा जा सकता है। सरकार ने नये प्रावधानों में निर्देश दिया है कि किसी भी अवैध या भ्रामक एआई जनित सामग्री को तीन घंटे के भीतर हटाना होगा या फिर ब्लॉक करना होगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले यह हटाने की समय सीमा 36 घंटे थी। हालांकि, इस तरह सख्त नियमों के जरिये सोशल मीडिया का नियमन खासा जटिल कार्य है। इस आदेश की जटिल कार्यप्रणाली के अतिरिक्त,यह सवाल भी विवाद का विषय बना हुआ कि ऑनलाइन आपत्तिजनक सामग्री किसे माना जाए। साथ ही यह भी कि क्या स्वीकार्य है? यदि हां तो किस आधार पर? वहीं दूसरी ओर इसके बहाने सरकारों द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की चिंताएं भी बरकरार हैं। सही मायनों में, लोकतंत्र की अपरिहार्य शर्त स्वतंत्र अभिव्यक्ति से जुड़ी इन चिंताओं का निराकरण भी जरूरी है। निस्संदेह दुनिया में जैसे-जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता डिजिटल क्षेत्र में अपना दायरा बढ़ाती जा रही है, वैसे-वैसे ही प्रभावी नियामक नियंत्रण स्थापित करना एक कठिन चुनौती बनता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर एआई उद्योग के लिये भी, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में अपनी तकनीकों के विस्तार के साथ-साथ नैतिक ढांचों को बनाये रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बनता जा रहा है।

चिंतन-मनन

भगवान की नज़र में हर इनसान बराबर है

इतिहास के पन्नों को उलट करके देखेंगे तो पाएंगे कि आज जितना ऊंच-नीच एवं अमीर-गरीब का भेद-भाव है वह वैदिक काल के आरंभ में नहीं था। उस समय सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्म के अनुसार वर्ग विभेद किया गया। लेकिन बाद में व्यवस्थाओं में जटिलता आती गयी और भेद-भाव बढ़ता गया। लेकिन यह भेद-भाव ऊपरी स्तर पर है। मूल में कहीं भेद-भाव नहीं है। मूल ईश्वर है और ऊपरी दुनिया वह है जहां हम मनुष्य और जीव-जन्तु विचरण करते हैं। भगवान की नजर में सभी एक समान हैं। ईश्वर की दृष्टि में न तो जात-पात है और न लिंग भेद। श्री रामानंदाचार्य ने कहा है जात-पात पूछे न कोई। हरि को भजे सो हरि का होई।। भगवान कभी किसी के साथ किसी आधार पर भेद-भाव नहीं करते हैं। केवट ने भगवान से प्रेम किया तो भगवान बिना किसी भेद-भाव के केवट की नैया में बैठे और केवट की जीवन नैया को पार लगा दिया। श्री राम के चरण रज को पीकर केवट परम पद पाने में सफल हुआ। भगवान की दृष्टि में सभी बराबर हैं इसका उदाहरण भक्त सबरी के जीवन की एक घटना है। सबरी भील जाति की एक महिला थी। राम की भक्ति इनके मन में ऐसी बसी की राम में ही खुद को अर्पित कर दिया। एक बार सबरी मार्ग में झाड़ू लगा रही थी उस समय साधुओं का एक समूह मार्ग से गुजरा। अनजाने में सबरी का स्पर्श साधुओं से हो गया। साधु इससे नाराज हुए कि एक भीलनी उससे स्पर्श कर गयी। भगवान को यह बात अच्छी नहीं लगी। साधुओं को जात-पात के भेद-भाव की नासमझी को दूर करने के लिए भगवान ने एक लीला की। साधुगण जिस सरोवर में स्नान करते थे। उस सरोवर में जैसे ही साधुओं ने प्रवेश किया सरोवर का जल दूषित हो गया। सरोवर के जल से बदबू आने लगी। साधुओं ने सरोवर के जल को शुद्ध करने के लिए कई हवन और यज्ञ किया लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। एक दिन सीता की खोज करते हुए भगवान राम जब सबरी की कुटिया में पधारे तब साधुओं को अपने ऊपर काफी ग्लानि हुई। उन्हें समझ में आ गया कि सबरी की भक्ति उनकी भक्ति भावना से बढ़कर है। सभी साधु सबरी की कुटिया में पधारे।

जातिगत भेदभाव पर बाजिव है विपक्ष की चिंता?

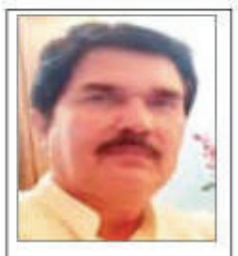

डॉ हिदायत अहमद खान

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसका संविधान है, जिसने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्शों को राष्ट्र जीवन का आधार बनाया। बावजूद इसके समय-समय पर जाति-संप्रदाय और धर्म के नाम पर भेदभाव किए जाने और हिंसा एवं मावलिंचिंग जैसी कष्टप्रद घटनाएं जब सामने आती हैं तो बेहद अफसोस होता है। ऐसी घटनाएं यह संकेत देती हैं कि संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक व्यवहार के बीच अब भी एक गहरी खाई मौजूद है। इस खाई को पाटने की बजाय और चौड़ी करने का कुत्सित कार्य गंदी राजनीति करने वाले तथाकथित नेता करते देखे जाते हैं। हर चुनाव से पहले इस पर चर्चा होती है और बदस्तूर घटनाएं भी होती हैं, इसलिए सभी कटघरे में खड़े होते हैं, फिर चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। बहरहाल राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाया गया जातिगत भेदभाव का मुद्दा इसी खाई की ओर ध्यान आकर्षित करता है। इस संदर्भ में विपक्ष की चिंता न केवल उचित है, बल्कि लोकतांत्रिक विमर्श का आवश्यक हिस्सा भी है। ओडिशा के एक आंगनवाड़ी केंद्र में दलित महिला द्वारा भोजन बनाए जाने के कारण बच्चों के बहिष्कार की घटना केवल एक स्थानीय विवाद नहीं मानी जा सकती। यह उस मानसिकता का प्रतीक है, जो आधुनिक भारत के विकास और प्रगति के दावों को चुनौती देती है। आंगनवाड़ी केंद्र देश के सबसे संवेदनशील सामाजिक संस्थानों में से हैं, जहां बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा की नींव रखी जाती है। यदि वहीं जातिगत पूर्वाग्रह के आधार पर बहिष्कार जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो यह न केवल एक कर्मचारी का अपमान है, बल्कि उन बच्चों के अधिकारों का भी हनन है, जिन्हें समान अवसर और पोषण मिलना चाहिए। यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि संविधान का अनुच्छेद 14 सभी को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है, जबकि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन की स्पष्ट घोषणा करता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 21(क) शिक्षा के अधिकार को सुनि त करता है और अनुच्छेद 47 राज्य को पोषण स्तर और जनस्वास्थ्य सुधारने की जिम्मेदारी सौंपता है। यदि जातिगत सोच के कारण पोषण कार्यक्रमों का बहिष्कार होता है, तो यह इन संवैधानिक प्रावधानों की भावना के विपरीत है। अतः ऐसे तमाम मामलों और घटित हुईं घटनाओं की जितनी निंदा की जाए कम होगी। राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने इस संबंध में जिन अन्य घटनाओं का उल्लेख किया उनमें मध्य प्रदेश में आदिवासी मजदूर के साथ अमानवीय व्यवहार, गुजरात में दलित कर्मचारी की आत्महत्या और चंडीगढ़ में संस्थागत भेदभाव जैसी घटनाएं भी शामिल हैं। ये मामले दशार्ते हैं कि समस्या केवल सामाजिक स्तर तक सीमित नहीं है। यदि संस्थागत ढांचे में भी पूर्वाग्रह मौजूद हैं, तो यह स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम जैसे कठोर कानूनों का अस्तित्व तभी सार्थक है, जब उनका प्रभावी और निष्पक्ष क्रियान्वयन हो। यह भी सच है कि जातिगत भेदभाव का मुद्दा अक्सर राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाता है। सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप होते हैं, जिससे मूल समस्या कभी-कभी राजनीतिक शोर में दब जाती है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मुद्दे की गंभीरता कम हो जाती है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका केवल आलोचना करना नहीं, बल्कि सरकार और समाज को आईना दिखाना भी है। यदि विपक्ष सामाजिक न्याय के प्रश्न को उठाता है, तो उसे केवल राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय व्यापक सामाजिक संदर्भ में समझा जाना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐसी घटनाओं को अलग-थलग घटनाएं कहकर टालने के बजाय उनकी जड़ तक पहुंचे। त्वरित और निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और पीड़ितों की सुरक्षा सुनि त करना आवश्यक है। साथ ही, सामाजिक जागरूकता अभियान चलाकर यह संदेश देना भी उतना ही जरूरी है कि जातिगत भेदभाव न केवल अवैध है, बल्कि नैतिक रूप से भी अस्वीकार्य है। विशेष रूप से आंगनवाड़ी, विद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में समानता और सम्मान के मूल्यों को व्यवहार में उतारने की जरूरत है। सामाजिक न्याय केवल विधायी प्रावधानों से स्थापित नहीं होता; वह समाज की मानसिकता में परिवर्तन से आता है। जब तक समाज के हर वर्ग में यह भावना विकसित नहीं होगी कि सम्मान और अधिकार जन्म से

नहीं, बल्कि अच्छे मानव होने के नाते मिलते हैं, तब तक कठोर कानूनों की आवश्यकता बनी रहेगी। बच्चों के सामने यदि समानता का व्यवहार प्रस्तुत किया जाएगा, तभी वे भविष्य में भेदभाव से मुक्त समाज का निर्माण कर सकेंगे। ऐसे में जातिगत ही नहीं बल्कि किसी भी प्रकार का भेदभाव जो समाज और समुदाय को तोड़ने का काम करता है वाला प्रश्न किसी एक दल या विचारधारा का नहीं, बल्कि भारतीय समाज की आत्मा का प्रश्न है। विपक्ष की चिंता इसलिए वाजिब है क्योंकि वह संविधान में निहित उस मूल भावना की याद दिलाती है, जिसे हम अक्सर भाषणों में दोहराते हैं पर व्यवहार में भूल जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि सामाजिक न्याय को राजनीतिक नारे से आगे बढ़ाकर राष्ट्रीय संकल्प बनाया जाए। तभी हम सही मायने में उस भारत की ओर बढ़ सकेंगे, जिसका सपना आजादी के दीवानों और संविधान निमार्ताओं ने देखा था।

जान के लिए खतरा बन रहे हैं लिव-इन रिलेशनशिप

मनोज कुमार अग्रवाल

हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिस में शार्ट फिल्मों में काम दिलाने के बहाने सनी युवतियों को शिकार बनाता था। इसके बाद उन्हें देह व्यापार के दलदल में धकेल देता था। पुलिस ने सनी के साथ उसकी मां रंजना और मां के प्रेमी प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात के मूल में लिवइन जिम्मेदार है।

आगरा के थाना खंदौली के यमुना एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा के पास शुक्रवार को कंबल में लपेटकर फेंके गए महोबा की सोनाली के शव के मामले में पुलिस ने महिला के साथ लिव इन में रहने वाले प्रेमी सनी, उसकी मां रंजना और मां के प्रेमी प्रदीप को जेल भेजा है। मामले में मृतका की बहन भारती ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पूछताछ में सामने आया है कि सनी शार्ट फिल्मों में काम दिलाने के बहाने युवतियों को जाल में फंसाकर देहव्यापार करवाता था। दूसरी युवती से दोस्ती का विरोध करने पर उसने सोनाली की हत्या कर दी थी। दूसरा मामला मध्यप्रदेश में इंदौर के सुगनीदेवी कॉलेज परिसर में गंभीर हालत में मिली युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवती को राहगीरों ने घायल अवस्था में एमवाय अस्पताल पहुंचाया था। उसके हाथों और शरीर पर कई टैटू बने हुए थे, वहीं शरीर पर ब्लेड से काटने के निशान भी पाए गए थे। शुरूआती जांच में डॉक्टरों को उसके साथ ज्यादती की आशंका हुई, जिसके चलते सैंपल भी लिए गए थे।

पुलिस जांच में सामने आया कि युवती पर हमला उसके लिव-इन पार्टनर ने किया था। आरोपी ने हत्या की नीयत से पत्थर से वार किया था। देर रात इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया।

लिव-इन रिलेशनशिप या सहमति संबंध एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें स्त्री-पुरुष बिना विवाह किए पति-पत्नी की भांति रहने के साथ-साथ आपस में शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं व कई तो बच्चे भी पैदा कर लेते हैं।

आपसी सहमति से कायम ऐसे संबंध पि मी देशों में आम बात है। उनकी देखा-देखी भारत जैसे देशों में भी यह बुराई फैलने लगी है, जिसके दुखद परिणाम निकलने लगे हैं। लिव-इन रिलेशन में रहने वाले अपने पार्टनर की हत्या करने से भी संकोच नहीं करते पिछले दिनों में लगातार ऐसी वारदातों की झड़ी लगी हुई है।

आपको ऐसी कुछ और वारदातों से अवगत कराते हैं 27 नवम्बर, 2025 को दिल्ली के छावला इलाके में वीरेंद्र सिंह नामक व्यक्ति को जब उसकी लिव-इन पार्टनर ने शराब पीने से रोका तो वीरेंद्र सिंह ने गुस्से में आकर उसका गला दबा दिया जिससे उसकी मौत हो गई।

30 नवम्बर, 2025 को चेन्नई (तमिलनाडु) में अपने पति को छोड़ कर गोविंदराज नामक व्यक्ति के साथ लिव-इन में रहने वाली प्रियंका नामक युवती ने किसी बात पर विवाद के चलते गोविंदराज को मार डाला।

8 दिसम्बर, 2025 को लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में रत्ना नामक विधवा ने अपनी 18 और 14 वर्षीय 2 बेटियों की सहायता से अपने लिव-इन प्रेमी सूर्य प्रताप सिंह की गला काट कर हत्या कर दी और पुलिस को बताया कि वह उसकी बड़ी बेटी पर बुरी नजर रखता था।

4 जनवरी, 2026 को ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में दक्षिण कोरिया के एक नागरिक की चाकू से गोद कर हत्या कर देने के आरोप में उसकी मणिपुर निवासी लिव-इन पार्टनर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार मृतक शराब पीने का आदी था और अक्सर युवती से मारपीट करता था जिसका अंजाम इस दुखद घटना के रूप में निकला। 8 जनवरी, 2026 को झांसी (उत्तर प्रदेश) में प्रीति नामक महिला के साथ लिव-इन में रह रहे रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी राम सिंह को प्रीति की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।12 जनवरी, 2026 को गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में आरती नामक महिला की हत्या के आरोप में उसके लिव-इन पार्टनर प्रवीण कुमार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार दोनों में शराब पीने के बाद किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया जिस पर प्रवीण कुमार ने आरती की पसलियों और छाती पर ताबड़तोड़ वार कर-के उसे मार डाला।18 जनवरी, 2026 को बिजनौर (उत्तर प्रदेश) के चांदपुर मेंशीतल नामक एक महिला ने अपने लिव-इन पार्टनर हरिओम सिंह की हत्या कर दी। पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान शीतल ने बताया कि रिलेशन के दौरान जब उसे गर्भ ठहरा तो हरिओम सिंह ने उसका गर्भपात करवा दिया और शादी के लिए बार-बार कहने पर भी वह मान नहीं रहा था। इस कारण वह नाराज होकर 15 जनवरी को अपने घर चली गई थी।घटना के दिन वह चांदपुर लौटी। दोनों ने पहले शराब पी। फिर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और शीतल ने शादी के लिए दोबारा दबाव बनाया तो हरिओम ने खुद को फांसी लगाने की धमकी देते हुए घर के बैड पर खड़े होकर अपने गले में फंदा डाल लिया। यह देख गुस्से में आई शीतल ने उसके पैरों में यह कहते हुए लात मार दी कि मैं ही तुझे मार देती हूं।

इससे वह फांसी पर झूल गया और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद वह मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ शव को खुद ही अपने साथ लेकर अस्पताल पहुंची और आत्महत्या की कहानी गढ़ दी लेकिन अंततः उसका भेद खुल गया और शीतल पकड़ी गई।

उच्च प्राचीन भारतीय संस्कृति को देखते हुए निःसंकोच यह बात कही जा सकती है कि लिव-इन रिलेशन किसी भी दृष्टि से भारतीय परिवारों के अनुकूल नहीं है। यह एक ऐसी बुराई है जिसका परिणाम दुखद ही निकलता है। अतः इस तरह के रिश्ते बनाने से बचना ही बेहतर है।आए दिन हो रही वारदातों से पता चलता है कि लिव-इन रिलेशनशिप की बुनियाद बेहद खोखले आपसी स्वार्थ और कपट पर टिकी हुई है और भारतीय समाज में अपराध को जन्म दे रही है।

बहरोड़ पुलिस की बैंक अधिकारियों व ज्वेलर्स के साथ बैठक, चोरी व साइबर ठगी रोकने पर जोर

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा बहरोड़

थाना परिसर में गुरुवार को एसएचओ अंकित सामरिया ने सरकारी व निजी बैंक अधिकारियों, ज्वेलर्स और प्रमुख प्रतिष्ठानों के संचालकों की बैठक ली। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में बढ़ती चोरी और साइबर ठगी की घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करना रहा। बैठक में एसएचओ ने सभी संस्थानों को रात्रि के समय सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से बैंक और ज्वेलरी प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड तैनात करने, उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे ऐसे स्थानों पर लगाए जाएं, जहां से प्रवेश और निकास द्वार स्पष्ट दिखाई दें। साइबर अपराधों में बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त करते हुए एसएचओ ने बैंक अधिकारियों को ग्राहकों को साइबर ठगी से बचाव के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बैंक में आने वाले लोगों को ओटीपी, एटीएम पिन और बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी से साझा नहीं करने तथा संदिग्ध कॉल और लिंक से सतर्क रहने की जानकारी दी जाए। एसएचओ ने कहा कि पुलिस और बैंकिंग संस्थानों के समन्वय से ही अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों ने पुलिस प्रशासन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

पलावा में विराट हिंदू सम्मेलन, कुटुंब प्रबोधन व सामाजिक समरसता पर जोर

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा मुंडावर

कस्बे के समीपवर्ती गांव पलावा में गुरुवार को संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में माणका मंडल की ओर से विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सकतपुरा, मिर्जापुर, बीरोद और माणका सहित आसपास के गांवों के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मिर्जापुर से निकली कलश यात्रा से हुई, जिसमें बीरोद, मिर्जापुर और पलावा की 851 महिलाओं ने भाग लिया। राधा-कृष्ण, शिव-पार्वती और हनुमान जी की झांकियों के साथ यात्रा बाबा खेतानाथ खेल मैदान पहुंची, जहां मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। सम्मेलन के मुख्य अतिथि कुंदन दास आश्रम के महंत धाकड़ दास महाराज रहे, जबकि अध्यक्षता महंत धर्मानंद सरस्वती ने की। मंच संचालन अभिषेक कौशिक ने किया। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक अक्षय कुमार ने हिंदू समाज से जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर एकजुट होने, परिवार संस्था को मजबूत करने और सामाजिक समरसता बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और युवाओं को मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से बचने की सलाह दी। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने सांस्कृतिक गौरव की रक्षा का संकल्प लिया। सम्मेलन में रणवीर यादव, ऋतुराज यादव सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।

ट्रक की टक्कर से लैब टेक्नीशियन की मौत, दो घायल

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा अलवर

अलवर में गुरुवार रात तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से हुए सड़क हादसे में एक लैब टेक्नीशियन की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सामोला चौक से आगे रूपबास ओवरब्रिज के पास रात करीब 9 बजे हुआ। पुलिस के अनुसार मृतक जाकिल (25) पुत्र मोहम्मद अख्तर खान निवासी रानीका, थाना नगीना, जिला नूंह का रहने वाला था। हादसे में उसके साथी महेंद्र गुर्जर और संतोष गुर्जर निवासी परसा का बास, मालाखेड़ा गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को राहगीरों की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर भूगोर तिराहे से सामोला चौक की ओर जा रहे थे। रूपबास ओवरब्रिज से उतरते समय ट्रक चालक ने लापरवाही से ओवरटेक करते हुए बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि जाकिल का सिर ट्रक के पहिए के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों अन्य युवक दूर जाकर गिरे। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। सूचना के करीब 45 मिनट बाद अरावली विहार और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज किया और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है।

राजस्थान स्टेट मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 27 फरवरी से

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा अलवर

अलवर में राजस्थान स्टेट मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 27 फरवरी से 2 मार्च तक किया जाएगा। प्रतियोगिता के मुकाबले इंदिरा गांधी स्टेडियम तथा स्कीम-8 स्थित बालभारती सीनियर स्कूल में आयोजित होंगे। इस प्रतियोगिता में प्रदेशभर से 300 से अधिक खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना जताई गई है। प्रतियोगिता में 35 वर्ष से अधिक, 40 वर्ष से अधिक, 45 वर्ष से अधिक, 50 वर्ष से अधिक, 55 वर्ष से अधिक, 60 वर्ष से अधिक, 65 वर्ष से अधिक, 70 वर्ष से अधिक और 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों के एकल, युगल और मिश्रित युगल मुकाबले नॉकआउट पद्धति से खेले जाएंगे। आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिता के चीफ रैफरी लोकेश सोनी होंगे। इस दौरान मार्च में जम्मू-कश्मीर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए राजस्थान टीम का चयन भी किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश स्तर के चयनकर्ता प्रतियोगिता स्थल पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा स्टेट अंपायर्स और मैच कंट्रोलर्स के लिए 25 व 26 फरवरी को लिखित और प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी जिला सचिव भविंद्र के पास अपना पंजीकरण करा सकते हैं। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में उत्साह देखा जा रहा है।

सैनी समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन 19 फरवरी को, 15 को होंगी प्रतियोगिताएं

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा अलवर

शहर में फुलेरा दूज के अवसर पर सैनी समाज की ओर से 19 फरवरी को प्याज मंडी परिसर में 29वें सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में 16 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। आयोजन को लेकर समाज में उत्साह का माहौल है और तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। समाज के महामंत्री पदमचंद सैनी ने बताया कि सम्मेलन से पूर्व 15 फरवरी को मेहंदी, रंगोली और फेंसी ड्रेस प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर एक बजे से तथा फेंसी ड्रेस प्रतियोगिता दोपहर दो बजे से शुरू होगी। प्रतियोगिताओं में प्रथम विजेता को वॉशिंग मशीन, द्वितीय को 32 इंच एलईडी टीवी और तृतीय विजेता को प्रेशर कुकर पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक प्रतियोगिता में 11 प्रतिभागियों का लकी ड्रॉ के माध्यम से चयन कर उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा। 19 फरवरी को आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में वन राज्य मंत्री संजय शर्मा मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के तहत सुबह 8:30 बजे काशीराम चौराहे से 16 दूल्हों की बारात निकाली जाएगी, जो सुबह 11 बजे प्याज मंडी परिसर पहुंचेगी। इसके बाद विवाह की सभी रस्में संपन्न कराई जाएंगी।

एलबीएस पीजी महाविद्यालय में खेल सप्ताह का शुभारंभ, विद्यार्थियों ने दौड़ प्रतियोगिताओं में दिखाया उत्साह

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा कोटपूतली

राजकीय एलबीएस पीजी महाविद्यालय में गुरुवार को उत्साहपूर्ण माहौल में खेल सप्ताह का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन प्राचार्य प्रो. आर.के. सिंह ने किया। उन्होंने विद्यार्थियों को खेलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि खेल जीवन में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना का विकास करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित रूप से खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। खेल सप्ताह के तहत छात्र-छात्राओं की 100 मीटर, 200 मीटर और 800 मीटर दौड़ प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। छात्र वर्ग की 100 व 200 मीटर दौड़ में देव गुर्जर प्रथम, साहिल कुमार वर्मा द्वितीय तथा सुमित रावत और हितेश सिंह शेखावत संयुक्त रूप से तृतीय स्थान पर रहे। 800 मीटर दौड़ में जॉनी सैनी प्रथम, हितेश सिंह द्वितीय और राहुल यादव तृतीय स्थान पर रहे। छात्रा वर्ग की 100 और 200 मीटर दौड़ में पायल चौधरी प्रथम, सुप्रिया द्वितीय तथा शोभा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिताओं के दौरान खेल मैदान में उत्साहपूर्ण वातावरण रहा और विद्यार्थियों ने खेल भावना का परिचय दिया। इस अवसर पर खेल अधिकारी मालीराम मीना सहित महाविद्यालय के संकाय सदस्य उपस्थित रहे। खेल सप्ताह के अंतर्गत आगामी दिनों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।

नारायणपुर में सिविल न्यायालय की मांग को लेकर दूसरे दिन भी अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार, कस्बे में निकाली बाइक रैली

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा नारायणपुर

कस्बे में एडवोकेट समीक गंगावत के सानिध्य में उपखंड स्तर पर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। तहसील कार्यालय के सामने चल रहे धरने के दूसरे दिन अभिभाषक संघ, डीड राइटर और स्टाम्प वेंडरों ने न्यायिक कार्यों का पूर्ण बहिष्कार किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अपनी बाइकों पर मांग से संबंधित तख्तियां लगाकर तहसील कार्यालय से मुख्य बाजार तक बाइक रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। एडवोकेट समीक गंगावत ने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार नारायणपुर में सिविल न्यायालय खोलने का निर्णय नहीं लेती, तब तक कार्य का बहिष्कार जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र ही सकारात्मक कदम नहीं उठाए तो इस आंदोलन को और अधिक उग्र रूप दिया जाएगा। अधिवक्ताओं ने बताया कि वे इस संबंध में क्षेत्रीय विधायक देवीसिंह शेखावत और मुख्यमंत्री के नाम पहले भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। न्यायालय के अभाव में स्थानीय पक्षकारों को न्यायिक कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उन्हें मानसिक और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वक्ताओं ने कहा कि यह स्थिति सरकार की सस्ती, सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने की मंशा के विपरीत है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान एडवोकेट रविंद्र शर्मा, रामकृष्ण चोपड़ा, लक्ष्मण प्रसाद दर्जी, तरुण तिवाड़ी, राहुल टेलर, कमलेश चौहान, रणजीत यादव, कैलाश चंद, श्योराम, मारुति प्रजापत, अर्जुन, राजेंद्र चोपड़ा, नरेंद्र शर्मा, सचिन गुर्जर, दाताराम सैनी और सुभाष प्रजापत सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

नीमराना में एनसीसी कमान अधिकारी कर्नल रनयोद्ध सिंह ने किया निरीक्षण, कैडेट्स को दी करियर गाइडेंस

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा नीमराना

कस्बे स्थित राव सोहन लाल पीजी महाविद्यालय में 9 राज बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी कर्नल रनयोद्ध सिंह और सूबेदार मेजर नूर मोहम्मद ने निरीक्षण, अवलोकन एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स को करियर गाइडेंस के साथ भविष्य निर्माण को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कर्नल रनयोद्ध सिंह ने अपने संबोधन में कैडेट्स को अनुशासन और समर्पण के साथ अपने भविष्य को संवारने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने युवाओं को भारतीय सेना में अधिकारी बनकर राष्ट्र सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया और एनसीसी के माध्यम से व्यक्तित्व विकास के महत्व पर जोर दिया। सूबेदार मेजर नूर मोहम्मद ने कैडेट्स को एनसीसी के उद्देश्यों, लक्ष्यों और इसकी उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने एनसीसी के बी और सी प्रमाण पत्र परीक्षाओं के महत्व तथा उनके माध्यम से मिलने वाले अवसरों से भी अवगत कराया। कार्यक्रम के दौरान कैडेट्स को अपने अनुभव साझा करने और शंकाओं का समाधान करने का अवसर मिला। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय चेयरमैन कृष्ण कुमार यादव ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर कौशल कुमार, प्रबंध निदेशक नीरज सिंह, कोऑर्डिनेटर प्रियंका यादव, कुलदीप, सतीश, नरेंद्र, राजेश चौधरी, निशा यादव सहित महाविद्यालय स्टाफ और एनसीसी कैडेट उपस्थित रहे।

बहरोड़ फ्लाईओवर के नीचे रेहड़ियों के लिए खींची लाल लाइन, जाम से मिलेगी राहत

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा बहरोड़

बहरोड़ में फ्लाईओवर के नीचे सर्विस रोड पर रोजाना लगने वाले जाम और अतिक्रमण की समस्या को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। थानाधिकारी अंकित सांवरिया और नगर परिषद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर फल-सब्जी की रेहड़ियों को व्यवस्थित करने के लिए लाल लाइन खिंचवाई। प्रशासन की ओर से सर्विस रोड से दोनों ओर करीब 30 फुट का रास्ता छोड़ते हुए लाल रेखा निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य मुख्य मार्ग पर यातायात को सुचारु बनाए रखना और बस स्टैंड क्षेत्र में लगने वाले जाम से लोगों को राहत दिलाना है। लंबे समय से अव्यवस्थित रेहड़ियों के कारण वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही थी, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नई व्यवस्था के तहत रेहड़ी संचालकों को निर्धारित सीमा के भीतर ही अपना सामान लगाने के निर्देश दिए गए हैं। थानाधिकारी अंकित सांवरिया ने विक्रेताओं को समझाते हुए कहा कि यातायात व्यवस्था बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है और नियमों की अवहेलना करने पर कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद अधिकारियों के अनुसार बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण और जाम की समस्या पर नियंत्रण के लिए यह व्यवस्था स्थायी समाधान के रूप में लागू की जा रही है। इस दौरान नगर परिषद के सहायक अभियंता राजेश कुमार टेलर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

शाहजहांपुर में श्रमिकों का प्रदर्शन, नए श्रम कानून के विरोध में उठाई आवाज

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा शाहजहांपुर

शाहजहांपुर में यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड के मुख्य गेट पर श्रमिकों ने नए श्रम कानून के विरोध में धरना-प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में श्रमिकों ने भाग लेकर अपने अधिकारों की सुरक्षा की मांग उठाई और सरकार व कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। श्रमिकों का कहना है कि नए श्रम कानून से उनके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, जिससे रोजगार सुरक्षा और कार्य परिस्थितियों को लेकर चिंता बढ़ गई है। उन्होंने सरकार से श्रमिक हितों की रक्षा सुनिश्चित करने और कानून की समीक्षा करने की मांग की। यह धरना-प्रदर्शन यूनाइटेड ब्रेवरीज श्रमिक एकता यूनियन के अध्यक्ष योगेश शर्मा के नेतृत्व में आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान हनुमान सिंह, प्रदीप कुमार, महेंद्र यादव, भगवान सहाय खारवाल, पोहप सिंह, कैलाश दान, विकास शर्मा, पवन और कुलदीप दुलीचंद सहित कई श्रमिक मौजूद रहे। यूनियन पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ।

बानसूर कृषि विज्ञान केंद्र में मशरूम उत्पादन पर प्रशिक्षण, किसानों को तकनीक व बाजार की जानकारी

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा बानसूर

बानसूर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में मशरूम उत्पादन तकनीक पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत हुए इस प्रशिक्षण में किसानों को मशरूम की खेती, उत्पादन तकनीक और बाजार की संभावनाओं से जुड़ी जानकारी दी गई। कार्यक्रम केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉ. सुशील शर्मा के निर्देशन और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. विजयवीर सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। पौध संरक्षण विशेषज्ञ डॉ. सुनील कुमार ने प्रतिभागियों को मशरूम के विभिन्न प्रकार, उनके पोषक तत्व, औषधीय गुण और बटन व आयस्टर मशरूम की खेती की तकनीक के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने खाद तैयार करने, बीज बुआई, उत्पादन कक्ष के रखरखाव और उत्पादन प्रक्रिया की जानकारी भी दी। विशेषज्ञों ने बताया कि मशरूम की खेती कम जगह, कम लागत और कम समय में तैयार होने वाली लाभकारी फसल है। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को प्रायोगिक रूप से मशरूम की बुआई और पॉलीथीन पैकिंग का प्रदर्शन भी कराया गया। कृषि विस्तार विशेषज्ञ डॉ. संदीप रस्तोगी ने मशरूम उत्पादों के मूल्य संवर्धन और बाजार संभावनाओं पर जानकारी दी। प्रशिक्षण में बानसूर तहसील के 42 किसानों ने भाग लिया, जिनमें 30 महिला किसान शामिल रहीं।

जरूरतमंद बालिकाओं के विवाह में भेंट किए बर्तन व दान का सामान

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा कोटपूतली

कोटपूतली के निकटवर्ती ग्राम खुर्दी में दो जरूरतमंद बालिकाओं के विवाह समारोह में सामाजिक सहयोग का सराहनीय उदाहरण देखने को मिला। गौ सेवक सरपंच विरेन्द्र गोठड़ी ने जरूरतमंद परिवार की बालिकाओं को बर्तन व अन्य दान का सामान भेंट कर सहयोग प्रदान किया। ग्रामीण मुकेश गुरूजी ने बताया कि खुर्दी निवासी सोनू वाल्मीकि की पुत्रियों मिनाक्षी और कोमल के विवाह के अवसर पर सरपंच विरेन्द्र गोठड़ी ने विवाह में उपयोगी बर्तन सहित अन्य आवश्यक सामग्री भेंट की। इस सहयोग से परिवार को आर्थिक राहत मिली और ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना की। ग्रामीणों के अनुसार विरेन्द्र गोठड़ी समय-समय पर जरूरतमंद और निर्धन परिवारों की सहायता करते रहते हैं। विशेष रूप से गरीब परिवारों की बालिकाओं के विवाह में सहयोग कर सामाजिक सरोकार निभा रहे हैं। इस अवसर पर मुकेश गुरूजी, राजेश कसाना, पी.सी. कसाना, एल.सी. कसाना, बल्लू कसाना, कमल रावत, विकास, सत्यवीर अवाना, बाबूलाल कसाना, प्रेम रैया सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने इसे समाज में सहयोग और संवेदनशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण बताया।

आक्रोशित राज्य कर्मचारियों ने बजट प्रतियों की जलाई होली, सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा कोटपूतली

राजस्थान बजट में कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी के विरोध में राज्य कर्मचारियों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर बजट प्रतियों की होली जलाई। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर हुए इस प्रदर्शन में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष महावीर शर्मा और महामंत्री महावीर सिहाग ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों का समाधान करने के बजाय उन्हें समितियों के जाल में उलझा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने दो वर्षों के कार्यकाल में कर्मचारी महासंघ से एक बार भी द्विपक्षीय वार्ता नहीं की। जिला संयोजक बाबूलाल गुर्जर ने कहा कि पिछली बजट घोषणा के बावजूद कैडर पुनर्गठन नहीं किया गया और इस बार भी पदोन्नति व वेतन विसंगति दूर करने के नाम पर केवल समिति गठन की घोषणा की गई है। उन्होंने संविदा और मानदेय कर्मियों के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं होने पर नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि मांगों का समाधान नहीं होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन में रामूतार गुर्जर, दिनेश शर्मा, प्रकाश गुर्जर, भीम सिंह, महेश, सतपाल, प्रताप सिंह सैनी, बुधराम कसाना सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे।

टी20 विश्वकप : कप्तान दासुन शनाका की रिकॉर्ड तोड़ पारी, टी20 विश्व कप में श्रीलंका ने ओमान को बुरी तरह हराया

नई दिल्ली (एजेंसी)। सह-मेजबान श्रीलंका ने पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के 16वें मैच में ओमान पर 105 रनों की शानदार जीत दर्ज की। कप्तान दासुन शनाका के रिकॉर्ड तोड़ अर्धशतक और शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन की बदौलत श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर टी20 विश्व कप 2026 की अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। कुसल मेंडिस (45 गेंदों में 61 रन), पवन रत्नायके (28 गेंदों में 60 रन) और दासुन शनाका (20 गेंदों में 50 रन) ने बल्ले से दबदबा बनाया, जबकि महेश थीक्षाना (4 ओवर में 2/11) और दुशमंथा चमीरा (20 ओवर में 2/19) ने गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन किया।

ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह द्वारा पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहे जाने के बाद, श्रीलंका ने पावरप्ले के दौरान शुरुआती झटके झेले, जिसमें कामिल मिश्रा (8) और पथुम निस्संका (13) आउट हो गए। हालांकि, ओमान द्वारा उलटफेर करने की कोई भी उम्मीद कुसल मेंडिस और पवन रत्नायके के बीच महज 50 गेंदों में खेली गई 94 रनों की तूफानी साझेदारी के सामने जल्द ही खत्म हो गई। रत्नायके ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए महज 28 गेंदों में 60 रन बनाए, जिसमें आठ चौके और एक छक्का शामिल था। 14वें ओवर में उनके आउट होने के बाद दासुन शनाका के आने से ओमान की टीम ने और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की।

शनाका ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए सिर्फ 19 गेंदों में श्रीलंकाई बल्लेबाज द्वारा टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक बनाने का सबसे तेज रिकॉर्ड कायम किया। पांच छक्के और दो चौकों सहित उनकी नाबाद पारी ने श्रीलंका को 20 ओवरों में 225/5 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया - जो टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर और पुरुष टी20 विश्व कप के इतिहास का चौथा सबसे बड़ा स्कोर है। 226 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए ओमान की बल्लेबाजी शुरू होने से पहले ही लड़खड़ा गई। दुशमंथा चमीरा ने पहले छह ओवरों में दो विकेट लेकर जतिंदर सिंह को एक रन पर और हम्माद मिर्जा को नौ रन पर आउट कर दिया।

अनुभवी मोहम्मद नदीम ने भले ही कुछ हद तक संघर्ष की उम्मीद जगाई हो, लेकिन चोटिल वानिंदु हसरंगा की अनुपस्थिति में श्रीलंका के स्पिन-प्रधान आक्रमण के सामने ओमान की टीम पूरी तरह से पस्त हो गई। नदीम की 56 गेंदों पर खेली गई 53 रनों की जुझारू पारी ने उन्हें टी20 विश्व कप इतिहास में अर्धशतक बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी का खिताब दिलाया, लेकिन यह ओमान के लिए काफी नहीं था। बढ़ते आवश्यक रन रेट के आगे मध्य क्रम बिखर गया, हालांकि महेश थीक्शाना और दुनीथ वेल्लालगे ने दबाव बनाए रखा। अंततः ओमान ने अपने 20 ओवरों में 120/9 का स्कोर बनाया, जो लक्ष्य से काफी कम था।

फ्रांसिस्को सेरुंडोलो अर्जेंटीना ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे

ब्यूनस आयर्स (एजेंसी)। लोकल फेवरेट और टॉप सीड फ्रांसिस्को सेरुंडोलो बुधवार को बोलीविया के ह्यूगो डेलियन को 6-0, 7-6 (6) से हराकर अर्जेंटीना ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। वर्ल्ड नंबर 19 सेरुंडोलो ने शुरुआती सेट में दम दिखाया और दूसरे सेट में आठ सेट पॉइंट बचाकर ब्यूनस आयर्स लॉन टेनिस क्लब के आउटडोर क्ले कोर्ट पर एक घंटे 24 मिनट में मैच अपने नाम कर लिया।

27 साल के सेरुंडोलो ने कहा, 'शुरुआत में चीजें जिस तरह से हुईं, उससे मैं खुश था लेकिन फिर उसने अग्रेसिव खेलना शुरू कर दिया और यह मुश्किल हो गया। मैंने कुछ सेट पॉइंट बचाए और मैं बस आगे बढ़कर खुश हूं।' सेरुंडोलो एटीपी 250 इवेंट के अगले राउंड में चेक रिपब्लिक के विट कोप्रिवा से भिड़ेंगे।

कोप्रिवा ने दिन में पहले इटली के आठवें सीड मातियो बेरेटिनी को 6-4, 6-3 से हराकर आगे बढ़े। बुधवार को दूसरे मैचों में, टॉमस एचेवेरी ने अर्जेंटीना के साथी रोमन बुरुचागा को 7-6 (5), 6-7 (3), 6-4 से हराया और चिली के एलेजांद्रो टेबिलो ने ब्राजील के तीसरे सीड जोआओ फोंसेका को 6-3, 3-6, 7-5 से हराया।

टी20 वर्ल्ड कप : मोस्का भाईयों की धमाकेदार बल्लेबाजी से इटली ने नेपाल को दस विकेट से हराया

मुंबई (एजेंसी)। मोस्का भाईयों की आक्रामक बल्लेबाजी से इटली ने आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 में नेपाल को दस विकेट से हराकर पहली जीत दर्ज की है। इटली की टीम की जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह पहली बार किसी आईसीसी टूर्नोमेंट में भाग ले रही है। उसे पहले मैच में स्कॉटलैंड ने आसानी से हरा दिया था पर इस मैच से उसने धमाकेदार वापसी की है। इस मैच में टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल ने 19.3 ओवर में 123 रन बनाये। इसके बाद जीत के लिए मिले लक्ष्य को इटली ने केवल 12.4 ओवर में ही 124 रन बनाकर हासिल कर लिया। टीम की ओर से जस्टिन मोस्का ने 44 गेंद में नाबाद 60 रन जबकि एंथनी मोस्का ने 32 गेंद में नाबाद 62 रन बनाये।

इस मैच में जीत के लिए मिले लक्ष्य का पीछा करते हुए मोस्का भाइयों ने तेज शुरुआत की और दोनो ने ही अर्धशतक लगाये। पहले चार ओवर में ही दोनों ने मिलकर 50 रनों से अधिक बना दिये। इसके बाद जब पावर प्ले में भी अच्छी बल्लेबाजी की। जस्टिन ने 44 गेंद में पांच चौके और तीन छक्के लगाकर नाबाद 60 रन जबकि एंथनी मोस्का ने 32 गेंद में 6 छक्के और 3 चौके लगाकर नाबाद 62 रन बनाये।

टी20 वर्ल्ड कप: ईशान किशन ने खेली धमाकेदार अर्धशतकीय पारी, रोहित-अभिषेक की बराबरी की

नई दिल्ली (एजेंसी)। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के सलामी बल्लेबाज़ ईशान किशन ने नामीबिया के खिलाफ ऐसी तूफानी पारी खेली, जिसने पावरप्ले बल्लेबाज़ी की नई मिसाल पेश कर दी। महज़ 20 गेंदों में अर्धशतक पूरा करते हुए किशन ने मैच की दिशा शुरुआती छह ओवरों में ही तय कर दी। 24 गेंदों पर 61 रन की उनकी आक्रामक पारी में चौकों-छक्कों की बारिश देखने को मिली। इस प्रदर्शन के साथ ईशान ने टी20 इंटरनेशनल में पावरप्ले में भारत के लिए 50 रन बनाने वाले चुनिंदा बल्लेबाज़ों की सूची में अपनी जगह और मजबूत कर ली।

पावरप्ले में 50 रन: खास क्लब में भारतीय बल्लेबाज

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहले छह ओवर यानी पावरप्ले सबसे अहम माने जाते हैं। इसी दौरान मैच की रफ्तार तय होती है। भारत की ओर से 1-6 ओवर के भीतर 50 रन बनाने का कारनामा बहुत कम बल्लेबाज कर पाए हैं। इस खास सूची में सबसे ऊपर अभिषेक शर्मा हैं, जिन्होंने यह उपलब्धि तीन बार हासिल की है। उनके बाद रोहित शर्मा और ईशान किशन का नाम आता है, जिन्होंने दो-दो बार पावरप्ले में 50 रन पूरे किए। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल भी एक-एक बार यह कमाल कर चुके हैं।

टी20आई में भारत के लिए 1-6 ओवर में फिफ्टी

अभिषेक शर्मा (तीन बार)
रोहित शर्मा (दो बार)
ईशान किशन (दो बार)
केएल राहुल (एक बार)
यशस्वी जायसवाल (एक बार)

नामीबिया के खिलाफ ईशान का तूफान

दिल्ली में खेले गए मुकाबले में ईशान किशन ने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर दिखाए। नामीबिया के गेंदबाज़ों पर दबाव बनाते हुए उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए। ईशान ने सिर्फ 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनकी पारी का सबसे खास पल रहा। उन्होंने कुल 24 गेंदों पर 61 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 5 शानदार छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 250 से अधिक रहा, जो टी20 क्रिकेट में बेहद प्रभावशाली माना जाता है। पावरप्ले के दौरान उनकी बल्लेबाजी ने भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया।

भारतीय ओपनिंग रणनीति का नया चेहरा

भारत ने पिछले कुछ वर्षों में पावरप्ले का अधिकतम फायदा उठाने की रणनीति अपनाई है। रोहित शर्मा और केएल राहुल जैसे अनुभवी बल्लेबाज़ों ने इसकी नींव रखी, जबकि अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल जैसे युवा खिलाड़ियों ने इसे आगे बढ़ाया। ईशान किशन का नाम इस सूची में शामिल होना

यह दर्शाता है कि वह बड़े मंच पर भी आक्रामक खेल दिखाने में सक्षम हैं। उनकी बल्लेबाज़ी शैली आधुनिक टी20 क्रिकेट की मांग के अनुरूप है—तेज रन, कम जोखिम और मैच पर शुरुआती नियंत्रण।

संजू सैमसन टी20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज भारतीय बने, देखें टॉप 5 खिलाड़ी

नई दिल्ली । आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए मुकाबले में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और नामीबिया आमने-सामने हैं। इस मैच में विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन ने आखिरकार टी20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच खेला और खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 31 साल 93 दिन की उम्र में डेब्यू करते ही वह भारत की ओर से टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार खेलने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए।

भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप में डेब्यू करने वाले उम्रदराज खिलाड़ी– संजू सैमसन का यह डेब्यू सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि एक आंकड़ों वाला मुकाम भी है। भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार खेलने के समय सबसे अधिक उम्र का रिकॉर्ड अमित मिश्रा के नाम है, जिन्होंने 2014 में पाकिस्तान के खिलाफ मीरपुर में 31 साल 117 दिन की उम्र में पहला मैच खेला था। सैमसन अब इस सूची में दूसरे नंबर पर हैं। उनसे नीचे सूर्यकुमार यादव (31 साल 40 दिन, 2021 बनाम पाकिस्तान), आशीष नेहरा (31 साल 2 दिन, 2010 बनाम अफगानिस्तान) और लक्ष्मीपति बालाजी (30 साल 358 दिन, 2012 बनाम अफगानिस्तान) आते हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि भारतीय टीम में टी20 वर्ल्ड कप डेब्यू का मौका कई बार अनुभवी खिलाड़ियों को भी देर से मिलता है।

बटलर ने सबसे ऊंचा कैच पकड़ने का विश्व रिकार्ड बनाया

मुम्बई । इंग्लैंड की टीम के विकेटकीपर जोस बटलर ने भारत में जारी टी20 विश्कप के दौरान सबसे ऊंचा कैच पकड़ने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इससे पहले ये रिकार्ड ऑस्ट्रेलिया के टिमोथी शैनन जेबेसीलन के नाम दर्ज था। टिमोथी ने सिडनी में 19 नवंबर 2021 को 119.86 मीटर करीब 393 फीट 2.897 इंच ऊंचाई वाला कैच पकड़ा था। बटलर ने ये रिकार्ड इंग्लैंड के ही पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन की देखरेख में बनाया है। बटलर के लिए सबसे ऊंचा कैच पकड़ना आसान नहीं था। उन्होंने करीब 60 मिनट तक इसके लिए तैयारी की थी और अंत में इसे पूरा किया। बटलर ने इसके बाद 122 मीटर ऊपर से ड्रोन से गिराए गए इस कैच को पकड़ा, ये तब लगभग 400 फीट जमीन से ऊपर था। गौरतलब है कि अभी तक किसी ने भी 120 मीटर से ऊपर का कैच नहीं पकड़ा है। बटलर को 60 मिनट इस रिकॉर्ड कैच के लिए मिले थे। 50 मीटर के कैच से उन्होंने शुरुआत की थी। पहले कुछ प्रयासों में तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। दगए वीडियो में बटलर केविन पीटरसन से ये कहते हुए भी नजर आए कि ये करना मुश्किल है, जबकि वर्ल्ड कप जीतना आसान है। बटलर ने ये भी कहा कि महेन्द्र सिंह धोनी और एडम गिलक्रिस्ट ने भी अब तक कभी इस प्रकार से कैच नहीं पकड़ा है। बटलर के लिए पहले गुलाबी गेंद हवा में ड्रोन से गिराई जा रही थी, जिसे वह पकड़ नहीं पा रहे थे तो उन्होंने सफेद गेंद से कैच पकड़ने के लिए कहा। सफेद गेंद से परेशानी पैदा कर रही थी तो उन्होंने फिर से लाल गेंद ली। इसके बाद 122 मीटर की दूरी वाला कैच पकड़ लिया और नया विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया।

टी20 विश्व कप : भारत के लिए चिंताजनक खबर, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेगा ये धमाकेदार बल्लेबाज !

नई दिल्ली(एजेंसी)। भारत के तूफानी सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया के खिलाफ खेले गए मैच के लिए प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा गया है। अमेरिका के खिलाफ पिछले मैच के दौरान उन्हें वायरल बुखार था, लेकिन फिर भी उन्होंने खेलने का फैसला किया। दिल्ली पहुंचने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई और पेट में संक्रमण का पता चला, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेडिकल जांच के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।

टॉस के समय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पुष्टि की कि अभिषेक ठीक हो रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से मैच फिटनेस हासिल करने में समय लगेगा। हालांकि वे टीम के साथ स्टेडियम पहुंचे, लेकिन उन्होंने अभ्यास नहीं किया और सिर्फ मैदान पर घूमते हुए नजर आए। कप्तान ने यह भी संकेत दिया कि सलामी बल्लेबाज पाकिस्तान के खिलाफ आगामी मैच में नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि उन्हें वापसी के लिए एक या दो और मैच खेलने की जरूरत पड़ सकती है। सूर्यकुमार ने टॉस के बाद कहा कि अभिषेक अभी पूरी तरह ठीक नहीं हैं, वे एक-दो मैच नहीं खेल पाएंगे। संजू टीम में आए हैं, वे भी अभिषेक जैसे ही विस्फोटक बल्लेबाज हैं। बुमराह सिराज की जगह आए हैं। बीसीसीआई ने भारतीय सलामी बल्लेबाज की सेहत के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मेडिकल टीम फिलहाल अभिषेक की सेहत पर नजर रख रही है। बीसीसीआई ने ट्वीट किया कि अभिषेक शर्मा अभी भी अपनी बीमारी से उबर रहे हैं और चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी सेहत पर कड़ी नजर रख रही है।

भारत के खिलाफ मुकाबले को लेकर हमपर कोई दबाव नहीं : फरहान

कोलंबो । पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने कहा है कि 15 फरवरी को भारतीय टीम के खिलाफ मुकाबले के लिए उनकी टीम तैयार है। फरहान ने कहा है कि इस महामुकाबले को लेकर उनकी टीम पर कोई दबाव नहीं है। पाक ने अपनी ग्रुप स्तर के शुरुआती मुकाबलों में नीदरलैंड और अमेरिका को हराया है। इसमें फरहान ने काफी अच्छी बल्लेबाजी भी की है जिससे उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। इसी को देखते हुए फरहान ने कहा कि दबाव भारतीय टीम पर अधिक होगा। इस बल्लेबाज ने कहा, जब आप दो लगातार मैच जीतते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आने वाला मैच कोई बड़ी बात नहीं है, हम भारतीय टीम के खिलाफ पहली बार नहीं खेल रहे हैं। पहले भी खेल चुके हैं। इस बार उनके खिलाफ हम अलग प्रकार की रणनीति के साथ खेलेंगे। उन्होंने कहा, आपने हमें पहले कठिन हालातों में और संघर्ष करते हुए देखा है पर अब जबकि शादाब और नवाज रन बना रहे हैं। इसलिए उम्मीद है कि ये मुकाबला रोमांचक होगा और इसका सभी को आनंद आएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ साल में हुए कई मैच एकतरफा रहे हैं और भारत ने आसानी से जीत हासिल की है। इसको लेकर फरहान ने कहा कि मुझे लगता है कि एशिया कप के दौरान हमारा मैच एकतरफा नहीं था। हम अंत तक खेले और लड़े। उम्मीद है कि इस बार हम और बेहतर खेल दिखाएंगे। फरहान ने कहा, मुझे लगता है कि जब आप रन बनाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। पिछली दो पारियों के बाद मेरा मनोबल भी बढ़ा है। भारत के खिलाफ मैच को हम एक आम मैच की तरह लेंगे और इसमें शांत दिमाग के साथ उतरेंगे। फरहान ने नीदरलैंड के खिलाफ पहले मैच में 47 रन जबकि अमेरिका के खिलाफ 73 रन बनाये थे।

लियोनेल मेस्सी चोटिल, इंटर मियामी के पहले मैच में खेलना संदिग्ध

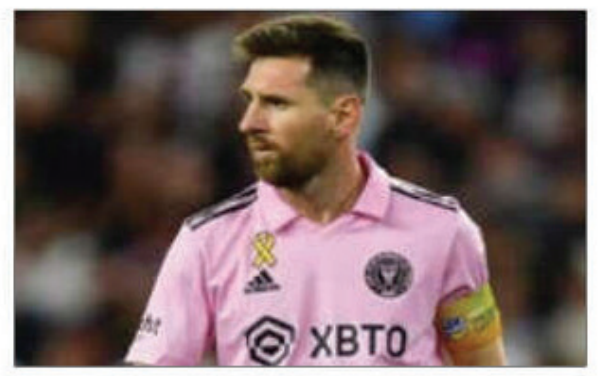

फोर्ट लॉडरडेल (अमेरिका)। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी की बायीं हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया है जिसके कारण उनका इंटर मियामी की तरफ से एमएलएस कप में 21 फरवरी को एलएएफसी के खिलाफ होने वाले सत्र के पहले मैच में खेलना संदिग्ध है। इंटर मियामी की टीम ने बुधवार को मेस्सी के चोटिल होने के बारे में जानकारी दी। एमएलएस के लगातार दो बार के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मेस्सी ने पिछले सप्ताहांत इक्वाडोर में सत्र से पहले खेले गए मैच में एक गोल किया, लेकिन दूसरे हाफ के लगभग 12 मिनट बाद उन्हें संभवत : हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण मैदान छोड़ना पड़ा था। इंटर मियामी ने एक बयान में कहा, 'अभ्यास में उनकी वापसी आने वाले दिनों में उनकी फिटनेस की प्रगति पर निर्भर करेगी।'

आईसीसी ने नबी पर जुर्माना लगाया

अहमदाबाद । अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाज मोहम्मद नबी पर आचार संहित उल्लंघन के मामले में जुर्माना लगाया है। नबी पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुए मैच में आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। यह नियम अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान अंपायर के निर्देश को न मानने से जुड़ा है। जुर्माने के अलावा नबी के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक नकारात्मक अंक भी जोड़ा गया है। पिछले 24 महीने में उनकी यह पहली गलती थी। यह मामला अफगानिस्तान की पारी के 14वें ओवर का है जब नबी की अंपायरों के साथ गेंदबाज लुंगी एनगिडी के कलाई बैंड को लेकर बहस हो गयी। नबी ने अपनी गलती मान ली है और एमिरेट्स आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय पैनल ऑफ मैच रेफरी के डेविड गिल्बर्ट की सजा को भी स्वीकार कर लिया है। ऐसे में आईसीसी की ओर से किसी औपचारिक सुनवाई की कोई जरूरत नहीं लगी है। इससे पहले मैदानी अंपायर जयरामन मदनगोपाल और शरफुद्दौला इब्ने शाहिद, थर्ड अंपायर नितिन मेनन और चौथे अंपायर के.एन. अनंथापद्मनाभन ने नबी पर आरोप लगाए थे। लेवल 1 के उल्लंघन के लिए आधिकारिक फटकार के अलावा खिलाड़ी की मैच फीस का 50 फीसदी जुर्माना और एक या दो नकारात्मक अंक दिये जाते हैं। अफगानिस्तान की टीम को इस मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे सुपर ओवर में हार का सामना करना पड़ा था।

पीएसएल 2026 सीज़न : स्टीव स्मिथ बने इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, सियालकोट स्टैलियंस से जुड़े

मुम्बई (एजेंसी)। पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के 11वें सीज़न से पहले हुए मेगा ऑक्शन ने क्रिकेट जगत में सनसनी फैला दी है। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को सियालकोट स्टैलियंस ने डायरेक्ट साइनिंग के तहत PKR 14 करोड़ (करीब 5 लाख अमेरिकी डॉलर) में अनुबंधित किया, जिससे वह क्क्रु इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। लीग के प्रारूप में बड़े बदलाव, दो नई फ्रेंचाइजी की एंट्री और ड्राफ्ट की जगह पहली बार ऑक्शन सिस्टम ने इस बार के सीज़न को और भी हाई-प्रोफाइल बना दिया है।

स्टीव स्मिथ की रिकॉर्डतोड़ डील

अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ स्टीव स्मिथ को नई टीम सियालकोट स्टैलियंस ने सीधे साइन किया। यह रकम PSL के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी को मिली सबसे बड़ी राशि है। स्मिथ, जो टी20 फॉर्मेट में अपनी स्थिरता और मैच कंट्रोल के लिए जाने जाते हैं, 11वें एडिशन में टीम के ब्रांड एंबेसडर और मुख्य बल्लेबाजी स्तंभ की भूमिका निभाएंगे। स्मिथ हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की टी20 विश्व कप टीम में चोटिल मिशेल मार्श की जगह लेने के कारण भी चर्चा में रहे। ऐसे में उनका PSL में आना लीग की ग्लोबल अपील को और मजबूत करता है।

ड्राफ्ट से ऑक्शन तक : PSL का बड़ा बदलाव

PSL ने इस सीज़न से ऐतिहासिक बदलाव करते हुए ड्राफ्ट सिस्टम की जगह प्लेयर्स ऑक्शन मॉडल लागू किया है। पिछले दस वर्षों से ड्राफ्ट फॉर्मेट में चल रही लीग अब इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की तरह बोली-प्रक्रिया के जरिए खिलाड़ियों को चुन रही है। लीग का विस्तार भी हुआ है–अब टीमों की संख्या छह से बढ़कर आठ हो गई है। सियालकोट और हैदराबाद दो नई फ्रेंचाइजी के रूप में शामिल हुई हैं। इससे प्रतियोगिता और व्यावसायिक आकर्षण दोनों में इजाफा होने की उम्मीद है।

ऑक्शन में विदेशी सितारों की चमक

लाहौर में आयोजित ऑक्शन में कई बड़े अंतरराष्ट्रीय नाम शामिल रहे। डेविड वार्नर, एडम ज़म्पा, डेरिल मिशेल, मार्क चैपमैन, मुस्तफिज़ुर रहमान, डेवोन कॉनवे, रिली रोसौ, तबरेज शमशी, दासुन शनाका, कुसल मेंडिस और मार्नस लाबुशेन जैसे खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइजियों ने दिलचस्पी दिखाई। कुल मिलाकर आठों टीमों ने 103 खिलाड़ियों को अपने स्क्वॉड में शामिल किया, जिससे आगामी सीज़न के लिए संतुलित और प्रतिस्पर्धी टीमें तैयार हुई हैं।

नसीम शाह सबसे महंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी

तेज़ गेंदबाज़ नसीम शाह इस ऑक्शन में सबसे महंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी बने। उन्हें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने PKR 8.65 करोड़ में खरीदा। उनके साथ ऑलराउंडर फहीम अशरफ भी उसी टीम में PKR 8.5 करोड़ में शामिल हुए। रिटेंशन में पेशावर जाल्मी ने बाबर आजम को PKR 7 करोड़ में बरकरार रखा, जबकि सबसे महंगा रिटेंशन सैम अयूब रहे, जिन्हें 12.2 करोड़ रुपये में रिटेन किया गया।

नई फ्रेंचाइजी और बड़े निवेश

सियालकोट और हैदराबाद फ्रेंचाइजी के राइट्स विदेशी पाकिस्तानी निवेशकों ने क्रमशः PKR 185,000 करोड़ और PKR 175,000 करोड़ में हासिल किए। नए स्वामित्व ढांचे के बाद मुल्तान सुल्तांस का भी पुनर्गठन हुआ और टीम का नाम बदलकर रावलपिंडी कर दिया गया। यह निवेश दिखाता है कि PSL अब वैश्विक क्रिकेट लीग्स में अपनी मजबूत आर्थिक स्थिति बना रहा है।

मेडिकल-सेल्स प्रतिनिधि लेबर कोड के विरोध में उतरे: 1976 के अधिनियम की रक्षा की मांग

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा हनुमानगढ़

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियनों की प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में मेडिकल और सेल्स प्रतिनिधियों ने भी सरकार की श्रम नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई है। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशंस ऑफ इंडिया (एफएमआरएआई) के सदस्यों ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया को ज्ञापन सौंपकर चारों लेबर कोड वापस लेने की मांग की है। संगठन के प्रतिनिधि दीपक शर्मा ने बताया कि देशभर के लाखों मेडिकल और सेल्स प्रमोशन कर्मचारी 12 संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच द्वारा बुलाई गई आम हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही नई श्रम संहिताएं मजदूर और कर्मचारी विरोधी हैं, जिनसे मौजूदा श्रम सुरक्षा कानून कमजोर होंगे। एफएमआरएआई का कहना है कि यदि चारों लेबर कोड लागू किए जाते हैं, तो सेल्स प्रमोशन इम्प्लॉइज (कंडीशन ऑफ सर्विस) एक्ट-1976 का दायरा सीमित हो जाएगा। यह अधिनियम मेडिकल और सेल्स प्रतिनिधियों की सेवा शर्तों, नौकरी की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करता है। संगठन के अनुसार, नई व्यवस्थाओं के तहत कंपनियों को सेवा शर्तों में मनमाने बदलाव का अधिकार मिल सकता है। इससे कर्मचारियों की नौकरी और सामाजिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। ज्ञापन में चारों लेबर कोड निरस्त करने, 1976 के अधिनियम को यथावत रखते हुए उसे और अधिक सशक्त बनाने तथा कर्मचारियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। इस दौरान विनोद गोयल, नील कालड़ा, नवनीत डोडा, गौरव सेतिया, गणेश चौधरी, बीके चौधरी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के अधिकारों की अनदेखी होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

डीडवाना में बीमा कर्मियों की एक दिवसीय हड़ताल

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा डीडवाना-कुचामन

डीडवाना में आज ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलाइज एसोसिएशन और संयुक्त मंच के आह्वान पर बीमा कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी एक दिवसीय हड़ताल की। डीडवाना शाखा के बीमा कर्मचारी भी इस हड़ताल में शामिल हुए और शाखा परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। शाखा अध्यक्ष एवं मंडल उपाध्यक्ष शंकरलाल वर्मा ने बताया कि यह हड़ताल सरकार द्वारा श्रम संहिताओं को अधिसूचित करने के विरोध में की गई है। इसके अलावा, बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई के प्रस्ताव, सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण और निगम में नई भर्तियों की मांग भी हड़ताल के प्रमुख कारण हैं। वर्मा ने आरोप लगाया कि नई श्रम संहिताओं की आड़ में कॉरपोरेट जगत को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे श्रमिक हित प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और 'हायर एंड फायर' जैसे नारों को श्रम व जनविरोधी बताया। शाखा सचिव सौरभ तिवाड़ी ने जानकारी दी कि संयुक्त मंच के आह्वान पर इस हड़ताल में बैंक, बीमा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों सहित कई संगठनों ने भाग लिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द उनकी मांगें नहीं मानीं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हड़ताल के दौरान शाखा के कई कर्मचारी उपस्थित रहे और अपनी मांगों के समर्थन में एकजुटता प्रदर्शित की।

सीकर के नीमकाथाना में सूटकेस में ब्लास्ट: संदिग्ध लग रहे दो लोग फरार

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा नीमकाथाना

सीकर जिले के गणेश्वर तीर्थ धाम पर गुरुवार को कुंड में फेंके गए सूटकेस में धमाका हो गया। घटना के वक्त कुंड परिसर में जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा था। घटना नीमकाथाना इलाके में गुरुवार दोपहर 2 बजकर 10 मिनट हुई। मजदूर सुरेश ने बताया - कुंड के पास निर्माण कार्य कर रहे थे। इसी दौरान दो लोग हाथ में एक सूटकेस और नारियल की थैली लेकर आए। उनमें से एक व्यक्ति किसी से फोन पर बात करते हुए कुंड में नारियल और सूटकेस डालने की बात पूछ रहा था। थोड़ी देर बाद ही उसने नारियल और बाद में सूटकेस कुंड में डाल दिया। जैसे ही सूटकेस डाला, जोरदार धमाके के साथ ही वहां धुआं फैल गया। धमाका होते ही वहां काम कर रहे मजदूर घबराकर जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग गए। मजदूरों के अनुसार, धमाका इतना तेज था कि सूटकेस के टुकड़े हो गए। धमाके के बाद दोनों संदिग्ध व्यक्ति भी वहां से भाग गए। डीएसपी सुशील मान ने बताया - प्रत्यक्षदर्शी मजदूरों से बात की गई है। मामले की जांच की जा रही है। धाम परिसर को खाली करवाया गया है। पुलिस ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू की और मौके से साक्ष्य जुटाए।

मेवाड़ यूनिवर्सिटी में नर्सिंग कोर्स की मान्यता को लेकर कश्मीरी छात्रों का अधर में भविष्य, 33 छात्र सस्पेंड

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी में नर्सिंग कोर्स की मान्यता को लेकर चल रहा विवाद अब गहरा गया है. अपनी डिग्री के भविष्य को लेकर प्रदर्शन कर रहे 33 कश्मीरी छात्रों को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया है. चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह शिक्षा नहीं बल्कि छात्रों का आक्रोश है. यूनिवर्सिटी के बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में पढ़ रहे 50 से ज्यादा कश्मीरी छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है. आरोप है कि जिस कोर्स में छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, उसे न तो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल और न ही इंडियन नर्सिंग काउंसिल से जरूरी अप्रूवल मिला है.

कोर्स को आरएनसी और आईएनसी से मान्यता नहीं

छात्र बाबर ने बताया कि वे 2022 बैच के स्टूडेंट हैं और इस समय उनका फाइनल ईयर चल रहा है. मार्च में उनकी अंतिम परीक्षा होनी है, लेकिन अब तक कोर्स को आरएनसी और

आईएनसी से मान्यता नहीं मिली है. उनका कहना है कि अगर कोर्स को मान्यता नहीं मिली तो उनकी डिग्री बेकार हो जाएगी. वे न तो प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे और न ही नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे. छात्र पहले भी 2024 में इसी मुद्दे पर विरोध कर चुके हैं. उस समय यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने कोर्ट में लिखित आश्वासन दिया था कि 4 दिसंबर 2024 तक अगर मान्यता नहीं मिली तो छात्रों को किसी अन्य मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में उसी स्कॉलरशिप पर शिफ्ट कर दिया जाएगा. लेकिन अब 2026 आ गया है और छात्रों के अनुसार अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. इस पूरे मामले में केवल 33 नहीं, बल्कि 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स प्रभावित बताए जा रहे हैं. फिलहाल छात्र प्रतिनिधियों ने केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की है ताकि इन 50 छात्रों का करियर तबाह होने से बच सके. छात्रों के प्रदर्शन पर गंगरार पुलिस मौके पर पहुंची

समय की कमी से बढ़ी चिंता

स्टूडेंट्स का कहना है कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। फाइनल सेमेस्टर चल रहा है और कुछ ही महीनों में परीक्षा है। ऐसे में वे बार-बार 'हमें समय दीजिए' का जवाब सुन-सुनकर परेशान हो चुके हैं। उनका कहना है कि जब परीक्षा सिर पर है तो और इंतजार करना उनके लिए संभव नहीं है। इसी कारण उन्होंने दोबारा आंदोलन शुरू किया। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन केवल आश्वासन दे रहा है, लेकिन मान्यता लेने की दिशा में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहा। सस्पेंशन की कार्रवाई को छात्र अपनी आवाज दबाने की कोशिश बता रहे हैं। बुधवार को मैनेजमेंट की ओर से गंगरार थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के साथ भी स्टूडेंट्स की झड़प हुई है।

50 से ज्यादा स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर

इस पूरे मामले में केवल 33 नहीं, बल्कि 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स प्रभावित बताए जा रहे हैं। यदि कोर्स को रहष्ट और ह्रहष्ट से मंजूरी नहीं मिलती है तो इन सभी छात्रों की डिग्री की वैधता पर सवाल खड़े हो जाएंगे। बिना मान्यता के नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी वे सरकारी या निजी हॉस्पिटल्स में पंजीकरण नहीं करा सकेंगे। इससे उनकी नौकरी और करियर की संभावनाएं खत्म हो सकती हैं। मेवाड़ यूनिवर्सिटी पहले भी डिग्री विवादों को लेकर चर्चा में रह चुकी है। अब एक बार फिर नर्सिंग कोर्स की मान्यता को लेकर उठे सवालों ने छात्रों और उनके परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। छात्र मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मान्यता दिलाई जाए या फिर उन्हें किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में शिफ्ट किया जाए, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रह सके। इधर, मैनेजमेंट से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।

कर्मचारियों की हड़ताल, नए श्रम कानूम में बदलाव का विरोध: अजमेर रेलवे स्टेशन से रैली निकालकर किया प्रदर्शन

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा अजमेर

श्रम कानूनों में बदलाव के विरोध में कर्मचारियों ने एक दिवसीय हड़ताल कर अजमेर में जोरदार प्रदर्शन किया। अजमेर रेलवे स्टेशन से रैली निकालते हुए कर्मचारियों ने लेबर कोड वापस लेने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी की गई और सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की गई। राष्ट्रीय श्रम संगठनों के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर अजमेर में गुरुवार को संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति के बैनर तले कर्मचारी एक दिवसीय हड़ताल पर हैं। कर्मचारी विरोध करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर जिला कलेक्टर पहुंचे और जिला कलेक्टर लोकबंधु को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए नए श्रम कानून में बदलाव करने की मांग की गई। प्रदर्शन में रेलवे, बैंक, बीमा, पोस्ट, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सहित अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल हुए। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्पलॉइज यूनियन के मंडल सचिव मोहन चेलानी ने बताया कि देश के श्रमिकों के हितों से संबंधित 29 श्रम कानून को समाप्त करके 4 नए श्रम कानून को लागू करने से श्रमिकों में रोष है। पुराने श्रम कानून में संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के अधिकार संरक्षित थे। श्रम कानून की पालना के लिए उद्योगपति बाध्य थे। चेलानी ने बताया कि लेकिन नए श्रम कानून

में श्रमिक हितों से संबंधित मुद्दों पर श्रमिकों के हित शिथिल कर दिए गए हैं और उद्योगपतियों के हितों का अधिक ध्यान रखा गया है। श्रमिक संगठनों ने एक दिवसीय हड़ताल का निर्णय लिया। चेलानी ने बताया कि संगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिक यूनियनों के अधिकारों को ही संकुचित कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों की रक्षा की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। चेलानी ने कहा कि नए श्रम कानून 4 लेबर कोड में पुराने 29 श्रम कानून में श्रमिकों को प्राप्त सभी अधिकारों को शामिल करने की कार्रवाई की जाए। जिससे भारत देश की प्रगति के साथ-साथ देश के श्रमिक वर्ग का भी आर्थिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित हो सके।

16 साल का बच्चा एनिकट में डूबा: एक दिन पूर्व भैंस चराने गया था

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा उदयपुर

उदयपुर जिले के खेरोदा थाना क्षेत्र बरोड़ीया गांव 16 साल के बच्चे की एनिकट में डूबने से मौत हो गई। युवक भैंस चराने गया था। वापस नहीं लौटा। बाद में उसके एनिकट में डूबने का पता लगा तो सिविल डिफेंस टीम को बुलाया गया। खेरोदा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। एक घंटे की मशक्कत के बाहर मृतक का शव बाहर निकाला और पुलिस को सुपुर्द किया। पुलिस ने शव को हॉस्पिटल मोर्चरी रखवाया। जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। मृतक की पहचान 16 वर्षीय नरेन्द्र सिंह राणावत पुत्र अमरसिंह निवासी बरोडिया के रूप में हुई। युवक कैसे और क्यों डूबा। इसका पता लगाने के लिए पुलिस जांच में जुटी है। जानकारी अनुसार युवक अपने घर से बुधवार दोपहर को भैंस चराने निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। जबकि भैंसें घर आ गईं थीं। घर पर युवक के नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई तो उन्होंने इधर-उधर युवक की तलाश की। रातभर भी युवक को ढूंढा गया लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। दूसरे दिन गुरुवार को जब किसी ग्रामीण ने एनीकट के पास चप्पल पड़ी देखीं। तो उसे शक हुआ। उसने तुरंत परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने मौके पर पहुंचे और नरेन्द्र की चप्पल होना बताया। जिसके बाद उसके डूबने की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी। सिविल डिफेंस को भी बुलाया गया। जिसके बाद शव को बाहर निकाला। सिविल डिफेंस टीम में गोताखोर विपुल चौधरी, विजय नकवाल, नरेश चौधरी, दिव्यांशु वैष्णव भवानी शंकर वाल्मीकि, अरविंद सिंह राणावत और बोट ऑपरेटर व वाहन चालक कैलाश मेनारिया थे।

सरकार चाहती है जनता बीमारी से तड़प कर मर जाए राइट टू हेल्थ पर मंत्री खींवसर के बयान पर बोले डोटासरा

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा जयपुर

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राइट टू हेल्थ को लेकर सरकार के रुख पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि आज ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि जनता बीमारी में तड़पती रहे, उसे इलाज न मिले. यदि किसी मरीज की प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो परिजनों को पूरा भुगतान किए बिना शव तक नहीं दिया जाता. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है. डोटासरा ने कहा कि कर्मचारियों के लिए लागू आरजीएचएस योजना भी प्रभावित हो रही है. प्राइवेट अस्पताल इससे बाहर हो रहे हैं, फार्मेसियों को भुगतान नहीं हो रहा है और नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई बजट नहीं दिया जा रहा. कांग्रेस सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की पहल की थी, लेकिन अब दो-तीन जिलों में उन्हें बंद किया जा चुका है. उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे राजस्थान में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अराजकता का माहौल है और लोग परेशान हैं कि आखिर इलाज के लिए जाएं तो कहां जाएं. उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि हर व्यक्ति को बेहतर और सुलभ इलाज मिले, बिना किसी आर्थिक शोषण के. डोटासरा ने कहा कि इससे अधिक शर्मनाक बयान नहीं हो सकता कि कांग्रेस

सरकार द्वारा 25 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की जो योजना लाई गई थी, उसका गला घोंट दिया गया. आरजीएचएस को भी कमजोर कर दिया गया और बड़े निजी अस्पतालों को खुली लूट की छूट दे दी गई. उन्होंने कहा कि यदि सरकार राइट टू हेल्थ कानून लागू नहीं करना चाहती तो स्पष्ट रूप से जनता को बता दे. यह बेहद निंदनीय है. कांग्रेस इस मुद्दे पर सड़क और सदन दोनों में आंदोलन करेगी और एक अभियान चलाएगी, ताकि जनता को बताया जा सके कि सरकार को लोगों के स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं है. डोटासरा ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट पिछले डेढ़ साल से सरकार से पूछ रहा है कि राइट टू हेल्थ कानून को लागू क्यों नहीं किया जा रहा, लेकिन सरकार वहां जवाब नहीं दे रही है और यहां सदन में चर्चा से बच रही है. यदि न्यायालय में लंबित मामलों पर चर्चा ही नहीं हो सकती

भारत-पाक सीमा पर फिर दिखा गुब्बारा: पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन्स लिखा हुआ गुब्बारा पुलिस ने जब्त किया

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा बीकानेर

जिले के सीमावर्ती क्षेत्र छतरगढ़ में एक बार फिर पाकिस्तानी गुब्बारा दिखाई दिया है। पहले भी कई बार ऐसे ही गुब्बारे सीमावर्ती क्षेत्र में मिले हैं, जिन पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन्स लिखा हुआ है। गुब्बारा मिलने की सूचना मिलते ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना कर दी। छतरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने गुब्बारे की स्थिति, उस पर लिखे शब्दों और उसके आसपास के क्षेत्र की बारीकी से जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह पहली बार नहीं है जब छतरगढ़ या बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में इस तरह के गुब्बारे मिले हों। इससे पहले भी कई बार बॉर्डर इलाके में पाकिस्तान की ओर से भेजे गए गुब्बारे बरामद हो चुके हैं। कई बार इन गुब्बारों पर अलग-अलग कंपनियों, संस्थानों या पाकिस्तान से जुड़े नाम भी लिखे मिले हैं। सीमा पार से ऐसे गुब्बारे अक्सर सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान भटकाने, क्षेत्र में भ्रम फैलाने या किसी संदिग्ध गतिविधि को अंजाम देने की मंशा से भेजे जाते हैं। ऐसे मामलों में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो जाती हैं

किसान-मजदूर संगठनों ने केंद्र सरकार को दी चेतावनी

नीतियां वापस नहीं ली तो होगा बड़ा संघर्ष, निजीकरण पर रोक और एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा उदयपुर

देश के किसान और मजदूर संगठनों ने एक बार फिर केन्द्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की समन्वय समिति के बैनर तले संयुक्त किसान मोर्चा और कई बड़े मजदूर संगठनों ने मिलकर उदयपुर में प्रदर्शन किया। टाउल हॉल से कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली गई। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। इस प्रदर्शन में हाथों में तख्तियां लिए महिलाएं भी शामिल हुई और महंगाई से राहत दिलवाने की मांग की। संगठनों का कहना है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को निजी हाथों में बेच रही है। इससे रोजगार के

अवसर खत्म हो रहे हैं और देश की आत्मनिर्भरता को खतरा पैदा हो गया है। इंटक प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली ने बताया- रेलवे, बिजली, बैंक और बीमा जैसे सेक्टर में निजीकरण की वजह से आम कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटक गया है। खासकर आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मिड-डे मील से जुड़े कर्मचारियों को न तो सही वेतन मिल रहा है और न ही उन्हें सामाजिक सुरक्षा दी जा रही है। सीटू के हीरा लाल सालवी ने बताया कि सरकार ठेका प्रथा को बढ़ावा देकर मजदूरों का शोषण कर रही है। किसानों की नाराजगी एमएसपी को लेकर बनी हुई है। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार अपने लिखित वादों से पीछे हट गई है। किसानों की मांग है कि उन्हें एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए ताकि वे बाजार के भरोसे न रहें। बिजली संशोधन बिल 2023 को लेकर भी विरोध तेज है। किसानों को डर है कि इस कानून के आने से खेती की लागत और बढ़ जाएगी और बिजली महंगी हो जाएगी। किसान आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों की वापसी और शहीद किसानों के परिवारों के लिए न्याय की मांग भी अभी तक अधूरी है। संगठनों ने भारत और अमेरिका के बीच होने वाले व्यापार समझौते पर भी सवाल उठाए हैं। इस तरह के समझौते बिना किसी पारदर्शिता के किए जा रहे हैं। इसका सीधा फायदा बड़ी विदेशी कंपनियों को होगा। इससे हमारे देश के किसानों को मिलने वाली सब्सिडी पर बुरा असर पड़ सकता है। बीजों पर से किसानों का हक छिन सकता है।

उद्धव ठाकरे का भाजपा पर निशानाः

निकाय चुनाव में हार के बाद बोले- वफादारी की दीवार को नहीं तोड़ सकता पैसा

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा नई दिल्ली

महाराष्ट्र में हाल ही में हुए सभी चुनावों में शिवसेना (यूबीटी) को हार का सामना करना पड़ा। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। उद्धव ठाकरे ने भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति पर निशाना साधते हुए कहा कि नगर निगम के चुनावों में खुब पैसा बहाया गया इसके बाद भी ये वफादारी की दीवार नहीं तोड़ पाए। 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के चुनावों में अधिकतर पर महायुति का दबदबा रहा। इसमें से कुछ सीटों पर चुने गए शिवसेना के सदस्यों और कार्यकर्ताओं से से हिम्मत न हारने और आगे की लड़ाइयों के लिए तैयार रहने को कहा। नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम में लगातार जीत के बाद, भाजपा ने जीत की 'हैट्रिक' हासिल की है, जिससे वह राज्य में नंबर वन पार्टी बन गई है। इसके उलट, महा विकास अघाड़ी को इस चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। हार मानते हुए, ठाकरे ने पार्टी सदस्यों और जीतने वाले उम्मीदवारों को हौसला बढ़ाने वाला मैसेज दिया। उन्होंने कहा आपने सच में चमत्कार किया है। आपने बहुत मुश्किल हालात में भी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने आगे कहा भले ही आज हालात ठीक न हों, भविष्य हमारा है। जिस हिम्मत से आपने ये चुनाव लड़े, वही हमारी असली ताकत है। महायुति ने ग्रामीण महाराष्ट्र में काफी बढ़त हासिल की है। जो राज्य की रीढ़ है। ठाकरे का बयान इस बात की ओर इशारा है कि वह नई ऊर्जा के साथ वापस मैदान में लौट रहे हैं। ठाकरे 2026 के ग्रामीण चुनावों की भी तैयारी में नजर आ रहे हैं। इन चुनावों को अगले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। लातूर, सांगली और छत्रपति संभाजीनगर जैसे जिलों में भाजपा के प्रदर्शन ने उसकी जमीनी पकड़ को मजबूत किया है। दूसरी तरफ, शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने कोस्टल बेल्ट में अच्छा प्रदर्शन किया, और एनसीपी (अजीत पवार) ने पश्चिमी महाराष्ट्र में अपनी पकड़ बनाए रखी।

पुणे में बंगाली मजदूर सुखन महतो की हत्या

सीएम ममता बोलीं- घृणात्मक अपराध; गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा कोलकाता

महाराष्ट्र के पुणे में एक बंगाली प्रवासी मजदूर की हत्या मामले में सियासत तेज हो गई है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना की कड़ी निंदा की और इसे भाषा और पहचान के आधार पर होने वाला घृणात्मक अपराध बताया। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस घटना का वीडियो साझा करते हुए लिखा कि वे इस क्रूर हत्या से स्तब्ध और गुस्से में हैं। बता दें कि 24 वर्षीय मृतक सुखन महतो बंगाल के पुरुलिया जिले के बंडवान के रहने वाले थे और अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। ममता बनर्जी ने कहा कि एक युवक को उसकी भाषा, पहचान और जड़ों के कारण मारा गया। सीएम ने आगे इस बात पर जोर दिया कि यह घृणात्मक अपराध सीधे उस माहौल का नतीजा है, जिसमें विदेशियों और अन्य राज्यों के लोगों के खिलाफ झूठे भय को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की। ममता बनर्जी ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि बंगाल इस कठिन समय में परिवार के साथ खड़ा है और न्याय दिलाने के लिए हर प्रयास किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह पहली बार नहीं है जब बंगाली प्रवासी मजदूरों के खिलाफ अन्य राज्यों में हिंसा हुई है और उन्होंने केंद्र सरकार पर भी लगातार इस मामले में चुप्पी बरतने का आरोप लगाया है। पुलिस और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, सुखन महतो 2021 से पुणे में प्रवासी मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। वे कोरेगांव भीमा के सनातबाड़ी क्षेत्र में एक कार पार्ट्स बनाने वाली कंपनी में कार्यरत थे। बुधवार दोपहर उनका शव शिकरपुर थाना क्षेत्र से बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि उन्हें बंगाली बोलने के कारण पीटा गया और मार दिया गया। उनके बड़े भाई तुलसीराम महतो ने इस संबंध में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है।

बांग्लादेश में 18 करोड़ लोगों की सरकार का दावा, जमात चीफ शफीकुर रहमान ने जताई जीत की उम्मीद

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा ढाका

बांग्लादेश चुनाव 2026 के बीच सियासी हलचल तेज हो गई है। कट्टरपंथी इस्लामी दल जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने गुरुवार को मतदान करने के बाद दावा किया कि यदि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न होते हैं, तो उनकी पार्टी जनादेश के आधार पर सत्ता हासिल कर सकती है। ढाका के मोनीपुर हाई स्कूल और कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर वोट डालने के बाद रहमान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे देश में ऐसी सरकार की उम्मीद करते हैं जो किसी व्यक्ति, परिवार या खास पार्टी की नहीं, बल्कि पूरे देश के 18 करोड़ नागरिकों की सरकार हो। स्थानीय अखबार द डेली स्टार के अनुसार, शफीकुर रहमान ने कहा अगर वोटिंग स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होती है, तो हम परिणाम स्वीकार करेंगे। दूसरों को भी जनता का फैसला मानना चाहिए। उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि चुनाव शांतिपूर्ण, हिंसा रहित और सभी पक्षों को स्वीकार्य हो। उनका कहना था कि देश को ऐसी सरकार की जरूरत है जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बने। हालांकि, चुनावी माहौल के बीच जमात-ए-इस्लामी पर गंभीर आरोप भी लगे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पार्टी से जुड़े लोगों ने मतदाताओं को कथित रूप से 15,000 बांग्लादेशी टका देने का प्रस्ताव रखा। रिपोर्ट्स के अनुसार, देशभर में ऐसे पर्चे बांटे गए जिनमें दावा किया गया कि जो परिवार पार्टी को वोट देंगे, उनकी अगली जिंदगी पाप मुक्त होगी और उन्हें गंभीर सजा से मुक्ति मिलेगी। एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि मतदाताओं से मतदान केंद्र पर कैमरा फोन लाने और बैलेट पेपर पर पार्टी के चुनाव चिह्न दारी पल्ला (तराजू) पर मुहर लगाने के बाद उसकी तस्वीर लेने को कहा गया। पर्चे में यह भी उल्लेख था कि चुनाव परिणाम आने के बाद वोटरों को बीकैश एप या नकद माध्यम से 15,000 टका भेजे जाएंगे

सुप्रीम फटकारः समाज के एक हिस्से को बदनाम नहीं कर सकते, पहले बदला हुआ नाम बताएं तभी 'घूसखोर पंडित' रिलीज होगी

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म 'घूसखोर पंडित' के फिल्ममेकर नीरज पांडे को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि ऐसे टाइटल का इस्तेमाल करके समाज के एक हिस्से को बदनाम नहीं कर सकते हैं। मनोज बाजपेयी स्टारर फिल्म 'घूसखोर पंडित' की रिलीज पर रोक लगाने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के नाम पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली थी।

नया नाम बताने के बाद ही रिलीज होगी फिल्म

पीटीआई की खबर के अनुसार जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जल भुयान की बेंच ने फिल्म 'घूसखोर पंडित' की एक याचिका पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सेंट्रल बोर्ड फॉर

फिल्म सर्टिफिकेशन को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा, 'आप ऐसे टाइटल का इस्तेमाल करके समाज के एक हिस्से को बदनाम क्यों कर रहे हैं? यह नैतिकता और पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है। जब तक आप हमें बदला हुआ नाम नहीं बताते हैं। हम आपको फिल्म रिलीज नहीं करने देंगे।' कोर्ट ने फिल्म मेकर्स को एक एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया कि 'घूसखोर पंडित' समाज के किसी भी वर्ग को नीचा नहीं दिखाती है। मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी।

याचिकाकर्ता ने फिल्म पर क्या लगाया था आरोप?

'घूसखोर पंडित' के खिलाफ दायर की गई याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह जाति और धर्म पर आधारित स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देती है। सांप्रदायिक सद्भाव और संवैधानिक मूल्यों के लिए खतरा पैदा करती है। यह याचिका भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय संगठन सचिव अतुल मिश्रा द्वारा फाइल की गई। इस पीआईएल पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस याचिका में फिल्म 'घूसखोर पंडित' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

फिल्म के नाम पर विरोध प्रदर्शन भी हुए

इस फिल्म को लेकर देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन भी हुए। कई फिल्म संस्थों ने भी इनके नाम को लेकर आपत्ति जताई। आखिर में मेकर्स ने नाम बदलने की बात कही। फिल्म 'घूसखोर पंडित' में मनोज बाजपेयी के अलावा नुसरत भरुचा, साकिब सलीम, अक्षय ओबेरॉय और दिव्या दत्ता जैसे कलाकार नजर आएंगे। बता दें कि बीते 03 फरवरी 2026 को नेटफ्लिक्स ने अपने साल 2026 के लिए 'इंडिया प्लान' का एलान किया। इसमें मनोज बाजपेयी की फिल्म 'घूसखोर पंडत' का एलान भी टीजर रिलीज करके किया गया। लेकिन इसकी टाइटल को लेकर विवाद शुरू हो गया है। लोग सड़कों पर उतर गए। इसके बाद यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया। फिल्म में मनोज बाजपेयी एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं। जिन्हें पुलिस महकमे में 'पंडत' कहा जाता है।

माल्या को हाईकोर्ट ने चेताया- भारत नहीं लौटे तो भगोड़ा होने के ठप्पे के खिलाफ सुनवाई नहीं

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा नई दिल्ली

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कारोबारी विजय माल्या को कड़ी चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि जब तक माल्या भारत वापस नहीं लौटते, तब तक अदालत उनकी उस याचिका पर सुनवाई नहीं करेगी। इस याचिका में उन्होंने भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओ) के प्रावधानों को चुनौती दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति खुद को न्यायिक प्रक्रिया से दूर रखे हुए है, उसे अदालत से राहत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की पीठ ने कहा कि माल्या को पहले यह स्पष्ट करना होगा कि वह भारत लौटेंगे या नहीं। कोर्ट ने कहा कि आपको (माल्या) वापस आना होगा...अगर आप वापस नहीं आ सकते तो हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते। 2016 से ब्रिटेन में रह रहे माल्या ने उच्च न्यायालय में दो याचिकाएं दायर की हैं, एक में उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के आदेश को चुनौती दी गई है और दूसरी में 2018 के अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया है। पीठ ने याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए 18 फरवरी की तारीख तय करते हुए कहा कि वह माल्या को यह स्पष्ट करने का एक और अवसर दे रही है कि क्या वह भारत लौटने के लिए तैयार है। अदालत ने कहा कि हमें यह दर्ज करना पड़ सकता है कि आप अदालत की प्रक्रिया से बच रहे हैं। आप कार्यवाही

का लाभ नहीं उठा सकते। आपके साथ निष्पक्षता बरतते हुए, हम याचिका खारिज नहीं कर रहे हैं बल्कि आपको एक और अवसर दे रहे हैं। अदालत ने दिसंबर 2025 में पिछली सुनवाई में अपना रुख स्पष्ट कर दिया था कि वह याचिका पर तभी सुनवाई करेगी जब माल्या भारत लौट आएंगे और उसने उनके वकील से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था। आज बेंच ने कहा कि कारोबारी को एक हलफनामा दाखिल करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वह भारत लौटेगा या नहीं। मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर ने कहा कि आप कब आएंगे? आप (माल्या) पहले ही यह तर्क दे चुके हैं कि आपको अदालत में शारीरिक उपस्थिति के बिना सुनवाई का अधिकार है। लेकिन पहले एक हलफनामा दाखिल करें जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा हो। माल्या की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने कहा कि ऐसे फैसले मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि याचिकाकर्ता की शारीरिक उपस्थिति के बिना भी ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई और फैसला किया जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि माल्या ने एफईओ घोषित किए जाने के बाद एफईओ अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती दी है। मेहता ने दलील दी कि मल्ल्या को पहले भारत आना चाहिए

चुनाव से ठीक पहले हिंदू युवक की हत्या, चाय बागान में मिली खून से लथपथ लाश; जांच में जुटी पुलिस

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा ढाका

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला मौलवीबाजार जिले से सामने आया है, जहां आम चुनाव से महज एक दिन पहले एक 28 वर्षीय हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। युवक का शव मिलने के बाद से इलाके मे तनाव का माहौल है। इस घटना ने वहां के अल्पसंख्यक समुदायों में डर और चिंता बढ़ा दी है। मृतक की पहचान रतन शुवो कर के रूप में हुई है। वह इस्लामपुर यूनियन के चंपारा चाय बागान में काम करता था। पुलिस को उसकी लाश हाथ-पैर बंधी हुई हालत में मिली। स्थानीय मीडिया के अनुसार, रतन के शरीर पर चोट के कई निशान थे और वह खून से लथपथ था। बांग्लादेश के जाने-माने अखबार, द डेली स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, लोकल लोगों ने बुधवार सुबह करीब 10:00 बजे चाय बागान के अंदर उसकी लाश देखी, जहां कर काम करता था। उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। रतन के साथ काम करने वाले लोगों का आरोप है कि उसे किसी दूसरी जगह मारा गया और फिर लाश को बागान में फेंक दिया गया। हालांकि, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। रतन के बड़े भाई लक्ष्मण कर ने बताया कि रतन मंगलवार रात से घर नहीं लौटा था। परिवार पूरी रात उसे तलाशता रहा। सुबह उन्हें बागान में लाश मिलने की खबर मिली। परिवार का कहना है कि उन्हें हत्या की वजह समझ नहीं आ रही है।

बांग्लादेश में इस समय चुनाव का माहौल है और राजनीतिक तनाव बना हुआ है। कुछ स्थानीय लोगों को शक है कि यह हत्या चुनाव से जुड़ी हो सकती है। पुलिस ने अभी इस बारे में कुछ भी साफ नहीं कहा है। अधिकारियों ने बताया कि मौत की असली वजह जानने के लिए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस हत्या का चुनाव से कोई लेना-देना है या इसके पीछे कोई और कारण है। इस घटना के बाद से इलाके में सुरक्षा और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। लगातार हो रही घटनाओं पर मानव अधिकार संगठन का कहना है कि हिंसा का स्तर चिंताजनक है। ह्यूमन राइट्स सपोर्ट सोसाइटी (एचआरएसएस) के मुताबिक, पिछले 17 महीनों में पॉलिटिकल हिंसा में कम से कम 195 लोग मारे गए और 11,229 घायल हुए। इनमें से लगभग आधी घटनाएं बीएनपी और उससे जुड़ी संस्थाओं के अंदरूनी झगड़ों की वजह से हुईं, जिनमें 121 मौतें हुईं और 7,131 घायल हुए। एक और राइट्स ग्रुप, ओधिकार ने इससे भी ज्यादा संख्या बताई, जिसमें कहा गया कि नौ अगस्त, 2024 और 31 दिसंबर, 2025 के बीच राजनीतिक हिंसा में 328 लोग मारे गए

सीएम के मानहानि केस पर अंतरिम रोक, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के साथ अन्यों की 9 मार्च को कोर्ट में पेशी

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा असम

असम के कामरूप जिले में एक अदालत ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के मानहानि केस पर अहम निर्देश दिया है। उन्होंने 500 करोड़ रुपये के मानहानि का एक केस दर्ज कराया था। इस मामले पर अदालत ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश देते हुए असम कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य गौरव

गोगोई पर सीएम की संपत्ति से जुड़ा कोई भी बयान देने से मना किया है। कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी इसी तरह के निर्देश दिए गए हैं। अदालत 9 मार्च को मामले में अगली सुनवाई करेगा। इस सुनवाई में गौरव गोगोई समेत सात लोगों को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि उनकी निजी संपत्ति और ईमानदारी के खिलाफ उन्हें बदनाम करने के लिए झूठे बयान दिए जा रहे हैं। इन्हीं आरोपों के साथ सीएम ने 500 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग करते हुए मानहानि का केस दर्ज किया था। इस विवाद पर पहले प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा था कि वह अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कानूनी उपाय करेंगे, और कहा था कि सार्वजनिक रूप से बयान देने की जवाबदेही होनी चाहिए। सबूत दिखाने का दावा करके कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। दूसरी ओर, कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि वे कानूनी प्रक्रिया जारी रहने के बावजूद सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं।

अजित पवार के विमान हादसे पर सवालः संजय राउत का केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर निष्पक्ष जांच न करने का आरोप

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा नई दिल्ली

महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने जांच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार के 'षड्यंत्र' और 'तोड़फोड़' के आरोपों का भी समर्थन किया। पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने केंद्र और राज्य की जांच एजेंसियों को घेरते हुए कहा, इस राज्य और देश की जांच एजेंसियां समझौता कर चुकी हैं। चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आईबी हो या राज्य पुलिस, जनता का इन पर से भरोसा उठ चुका है। उन्होंने कहा कि इस केंद्र सरकार के समय में बड़े मामलों की निष्पक्ष जांच नहीं होती। सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए जांच में पक्षपा करती है। उन्होंने कहा कि जो विमान हादसे का शिकार हुआ था वह गुजरात से आया था, जिससे लोगों के मन में संदेह पैदा हुआ है। जिस विमान में अजित दादा सवार थे, वह भी गुजरात से आया था। अहमदाबाद विमान हादसे को देखिए, लगभग 300 लोग मारे गए, लेकिन उसकी जांच का क्या हुआ? कोई बता सकता है कि वह विमान कैसे गिरा? राउत ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी अपील की कि वे रोहित पवार के आरोपों को गंभीरता से लें और उन्हें राजनीतिक बयानबाजी कहकर खारिज न करें। रोहित पवार तथ्यों के साथ विस्तृत जानकारी रख रहे हैं। अगर अजित दादा के निधन पर शोक सच्चा है, तो शिंदे को रोहित पवार और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक बुलानी चाहिए।

ओवैसी को संसद में आया गुस्सा

टैरिफ पर ट्रंप को लिया आड़े हाथ, भारत को बताने वाला गोरी चमड़ी वाला कौन?

वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा नई दिल्ली

लोकसभा में बुधवार का दिन भी हंगामे से भरा पूरा रहा। बजट, रूसी तेल और अमेरिका के साथ व्यापार समझौता समेत कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखे। हालांकि इस दौरान एआईएमआईएम प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी का रूसी तेल खरीद को लेकर अमेरिका की चेतावनी और डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर सवाल खड़े करना भी खूब चर्चा में रहा। ओवैसी ने इसे इसे भारत की संप्रभुता का अपमान बताते हुए सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर

हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत अगर भारत सीधे या परोक्ष रूप से रूस से तेल खरीदता है तो उस पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जाएगा। इसी मुद्दे पर लोकसभा में बोलते हुए ओवैसी ने ट्रंप को आड़े हथ लिया। ओवैसी ने तीखे अंदाज में पूछा कि ये कौन गोरी चमड़ी वाला है, जो वहां बैठकर हमें हुकुम देगा? हमारा जिससे मन करेगा उससे तेल खरीदेंगे, वो कई नहीं होते हमें बताने वाले। लोकसभा में चर्चा के दौरान ओवैसी ने कहा कि दुर्भाग्य है कि अभी तक भारत सरकार इस पर चुप है? कोई भी विदेशी नेता यह तय नहीं कर सकता कि भारत किस देश से तेल खरीदेगा। उन्होंने कहा कि देश ने आजादी इसलिए नहीं पाई थी कि कोई दूसरा देश बैठकर यह निर्देश दे कि भारत क्या खरीदे और क्या नहीं? इसी दौरान ओवैसी ने केंद्र सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि वह इस मुद्दे पर चुप क्यों है और भारत अपने आत्मसम्मान से समझौता क्यों कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी जरूरत और राष्ट्रीय हित के आधार पर फैसले लेने चाहिए, न कि किसी बाहरी दबाव में। ओवैसी ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के अलावा यूरोपीय संघ के साथ होने वाली संधि पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत ने मेडिकल उपकरणों और उन्नत मशीनरी जैसे उत्पादों पर टैरिफ कम कर दिए हैं, जिससे विदेशी सामान भारतीय बाजार में आसानी से आएगा। उनके मुताबिक, इससे देश में उद्योगों के कमजोर होने और 'डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन' का खतरा पैदा हो सकता है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक, संदीप कुमार के लिए कसाणा प्रिंटिंग प्रेस, नियर बस स्टैंड भिण्डुसी, तहसील- तिजारा, जिला- अलवर (राजस्थान) पिन कोड- 301405, से मुद्रित तथा 109, धर्मशाला के पास, वीपीओ- हींगवाहेड़ा, तहसील- तिजारा, जिला- अलवर (राजस्थान) पिन कोड- 301411 से प्रकाशित। संपादक, संदीप कुमार Mob- 9414508610 E-mail:- pratigya.alwar@gmail.com पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के लिए जिम्मेदार, समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र अलवर होगा